- वर्ष-3
- अंक-101
- रायपुर, बुधवार 06 दिसंबर 2023
- पृष्ठ-8
- मूल्य-3 रु.

samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› कंधों में जकड़न होती है तो करें..

लालदुहोमा बनेंगे मिजोरम के मुख्यमंत्री

नई दिल्ली। लालदुहोमा ने एक ऐसा तूफान आया जिसकी तेज से निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा सहित उनके प्रमुख नेता हवा में उड़ गए। सेरछिप से खुद लालदुहोमा ने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की है।

2023 के आखिर में पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों में सबसे ज्यादा चर्चा मिजोरम की हो रही है। दरअसल, मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट को दो तिहाई से ज्यादा बहुमत मिला है। इसके साथ ही वर्षों से राज्य में चली आ रही कांग्रेस और एमएनएफ सरकारों की जो परंपरा रही है वह भी टूट गया है। इसके साथ ही एक नाम की चर्चा जबरदस्त तरीके से हो रही है और वह नाम लालदुहोमा की है। लालदुहोमा जोरम पीपुल्स मूवमेंट के प्रमुख है और कहीं ना कहीं इन्हीं के नेतृत्व में पार्टी 27 सीटों पर जीत हासिल करने में सफल हुई है। लालदुहोमा ने एक ऐसा तूफान आया जिसकी तेज से निवर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा सहित उनके प्रमुख नेता हवा में उड़ गए। सेरछिप से खुद लालदुहोमा ने चुनाव जीतने में कामयाबी हासिल की है। ऐसे में दिलचस्प है कि आखिर लालदुहोमा कौन हैं, इनको लेकर इतनी चर्चा क्यों है? लालदुहोमा राज्य के नए मुख्यमंत्री बनने जा रहे। लालदुहोमा के बारे में अगर संक्षेप में जानकारी दें तो बस आप इतना जान लीजिए कि ये संघर्ष के दूसरे नाम हैं। संघर्ष करने से कभी पीछे नहीं हटते। तभी 73 वर्ष की उम्र में भी उन्होंने मिजोरम को लेकर एक मजबूत लड़ाई लड़ी है। 22 फरवरी 1949 को जन्मे लालदुहोमा ने बचपन से ही कई कठिनाइयों का सामना किया। संघर्षों के बीच अपनी पढ़ाई पूरी की। मैट्रिक की परीक्षा के बाद उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा हासिल की। शुरूआत में उन्होंने पूर्व सीएम सी चुंगा के शासन में साल 1972 में मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रधान सहायक के रूप में नौकरी की। उन्होंने 1977 में सिविल सेवा की परीक्षा दी और शानदार परफॉर्म करते हुए आईपीएस बन गए।

शुरूआत में उन्होंने तटीय राज्य गोवा में सेवा दी। लालदुहोमा ने गोवा में स्मगलर्स और ड्रग माफियाओं के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई की। उनके काम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को काफी प्रभावित किया। फिर उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित कर दिया गया जहां उन्होंने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा के प्रभारी के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। उन्हें डीसीपी की जिम्मेदारी भी दी गई। इसी दौरान उनका झुकाव राजनीति की ओर भी होने लगा।

गौमूत्र वाले बयान पर बवाल, कांग्रेस भड़की

नई दिल्ली। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के सांसद डीएनवी सेंथिल कुमार एस ने मंगलवार को संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में अपनी टिप्पणी से विवाद खड़ा कर दिया। राज्य विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की हालिया जीत का मजाक उड़ाते हुए, तमिलनाडु के नेता ने हिंदी हृदय राज्यों पर लक्षित अपमानजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा, भाजपा की ताकत मुख्य रूप से हिंदी भाषी राज्यों में चुनाव जीतने में है। आप दक्षिण भारत में नहीं आ सकते। सेंथिलकुमार की टिप्पणी जिसके कारण विवाद हुआ था, उसे संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया।

माफी नहीं मांगी- वीडियो के अनुसार धर्मपुरी से लोकसभा सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार ने लोकसभा में कहा, इस देश के लोगों को यह सोचना चाहिए कि इस भाजपा की ताकत मुख्य रूप से हिंदी के गढ़ राज्यों में चुनाव जीतना है, जिन्हें हम आम तौर पर गौमूत्र राज्य कहते हैं। विवाद बढ़ने के बाद भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने सदन के अंदर कुछ बयान दिया। उस समय गृह मंत्री और भाजपा

सदस्य वहां मौजूद थे। मैंने पहले भी अपने संसद भाषणों में इसका उपयोग किया है। यह कोई विवादास्पद बयान नहीं था। यदि यह किसी को छूता है तो मैं अगली बार इसका उपयोग करने से बचने का प्रयास करूंगा। मैं यह बताने के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग करूंगा कि भाजपा कहां वोट पाने में मजबूत है। वहीं, मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम)के सांसद वाइको ने कहा, मैं उनके बयान से सहमत हूं, वे सही हैं।

भाजपा हमलावर- सेंथिलकुमार के बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि यह सनातनी परंपरा का बहुत बड़ा निरादर है...सनातनी परंपरा और सनातनियों का इस तरहा का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा। चाहे छ्रख्र हो या कोई भी, जो देश की आस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसे जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि इस प्रकार की गंदी बातें करने वाले लोग, जो सनातन को गाली देते थे उन्हें अभी आधा तमाचा लगा है, थोड़े दिन बाद पूरा लगेगा... गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान देश नहीं सहेगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, जो जिस तरह से सोचते हैं वे उसी तरह कहते हैं, इसका भारत की जीवन पद्धति में कितना महत्व है उसका उन्हें अंदाज़ा नहीं है...। भाजपा सांसद सुशील मोदी ने कहा कि इस प्रकार की भाषा का खामियाजा उन्हें तीन राज्यों के चुनाव में भुगतना पड़ा है... ऐसी हल्की टिप्पणी करना उचित नहीं है, ऐसे लोगों को लोकसभा(चुनाव) में जनता सबक सिखाएगी।

कांग्रेस भी साथ नहीं- डीएमके सांसद डीएनवी सेंथिलकुमार एस की %गौमूत्र% टिप्पणी पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि संसद के अंदर एक व्यक्ति क्या कह रहा है, इससे हमारा कोई लेना-देना नहीं है, यह उनका अपना बयान है। हम %गौ माता% का सम्मान करते हैं, हम इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट किया, शब्दों का चयन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। असंसदीय। तुरंत माफी मांगनी चाहिए और अपनी टिप्पणी वापस लेनी चाहिए। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने कहा कि डीएमके की राजनीति अलग है। कांग्रेस उनकी राजनीति से सहमत नहीं है। कांग्रेस सनातन धर्म और गौमाता में भी विश्वास करती है। हम सभी धर्मों के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने में विश्वास रखते हैं। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि छ्रख्र के नेताओं की अगर यही हरकतें रही और सनातन धर्म के खिलाफ वे ऐसी ही बकवास करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में ही नहीं सांड वाले राज्यों में भी भाजपा का परचम लहरा जाएगा।

- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि देश में एक ध्वज, एक प्रधानमंत्री, एक संविधान की अवधारणा कोई राजनीतिक नारा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस सिद्धांत में दृढ़ता से विश्वास करती है तथा उसने जम्मू कश्मीर में आखिरकार यह कर दिखाया है। लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत राय ने कहा कि देश में 'एक निशान, एक प्रधान, एक संविधान' एक 'राजनीतिक नारा' था।

- कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सहित विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव यथाशीघ्र कराने की मांग लोकसभा में मंगलवार को की। विपक्षी दलों ने जम्मू कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 पर सदन में संयुक्त चर्चा के दौरान सरकार से मांग की कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द विधानसभा चुनाव की घोषणा की जाए। गृह मंत्री

कांग्रेस को मिला लालू का साथ बोले-

कमजोर नहीं हुई है पार्टी

17 को हो सकती है इंडिया की बैठक

नई दिल्ली। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यात्रा नहीं कर पाएंगे और बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चक्रवात मिचौंग के कारण चेन्नई हवाईअड्डा बंद है, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने सूचित किया था कि उनकी पहले से प्रतिबद्धताएं थीं। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) सुप्रीमो लालू यादव

ने मंगलवार को कहा कि विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन की बैठक 17 दिसंबर को होगी। पहले यह बैठक बुधवार को होनी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित शीर्ष नेताओं द्वारा इसमें शामिल होने को लेकर असमर्थता जताने के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन यात्रा नहीं कर पाएंगे और बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि चक्रवात मिचौंग के कारण चेन्नई हवाईअड्डा बंद है, नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं और ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने सूचित किया था कि उनकी पहले से प्रतिबद्धताएं थीं।

राज्यसभा में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सुधांशु त्रिवेदी ने वर्तमान विश्व परिदृश्य में अमेरिका और चीन जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर धीमी पड़ने की ओर ध्यान दिलाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की विभिन्न नीतियों के कारण हुए विकास के चलते अब विश्व की प्रमुख एजेंसियां भी कहने लगी हैं कि भारत विश्व अर्थव्यवस्था का 'लीडर' बनकर उभर रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है।

गौतम अडानी ने एक दिन में हासिल की बड़ी उपबल्धि

मुंबई। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी इन दिनों सातवें आसमान पर है क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयरों में बीते सप्ताह से ही तेजी का सिलसिला जारी है। पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही अडानी ग्रुप के शेयरों में लगातार इजाफा होता जा रहा है। शेयर बाजार में लगातार उछाल हो रहा है। इसके साथ ही अडानी ग्रुप के स्टॉक भी रॉकेट की रफ्तार से ऊपर की ओर भाग रहे हैं।

शेयर बाजार में लगातार हो रहे इस इजाफे के कारण गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। सिर्फ यही नहीं गौतम अडानी दुनिया के टॉप अरबपतियों की सूची में भी कई पायदान ऊपर आ गए हैं। जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को गौतम अडानी टॉप अरबपतियों की सूची में 20वें पायदान पर थे। वहीं सोमवार को चुनाव के नतीजे आने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों ने कमाल का परफॉर्मेंस किया है। शेयरों में इजाफा होने के बाद गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी इजाफा हुआ है। गौतम अडानी टॉप अरबपतियों की सूची में चार पायदान ऊपर पहुंच गए। इसी के साथ गौतम अडानी 16 वें पायदान पर आ चुके हैं। बता दें कि गौतम अडानी की नेटवर्थ में बीते 6 कारोबारी दिनों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का इजाफा हुआ है। चुनावी नतीजे के बाद गौतम अडानी ग्रुप के शहरों में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिला है जिसके बाद उनकी संपत्ति लगभग 3677 करोड़ रुपए बढ़ गई है।

प्रमुख समाचार

करणी सेना के अध्यक्ष की हत्या से क्षुब्ध समर्थक धरने पर

जयपुर. राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को अज्ञात हमलावरों ने श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की दिनदहाड़े उनके घर में घुस कर गोली मार कर हत्या कर दी। देखा जाये तो राजस्थान में कानून व्यवस्था की लचर हालत अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल की शुरुआत से ही शुरू हो गयी थी और इस सरकार के कार्यकाल के अंत तक वैसी ही स्थिति बनी रही। यदि अशोक गहलोत ने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की सुरक्षा दिये जाने की मांग मान ली होती तो आज शायद वह जिंदा होते। इसलिए सवाल उठता है कि सुखदेव सिंह की हत्या के असल जिम्मेदार कौन हैं? सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली लगने की खबर मिलते ही उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मृत्यु हो गयी। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गयी जिसको देखते हुए सुरक्षा प्रबंधों को पुख्ता किया गया है। इस बारे में पुलिस ने बताया है कि मंगलवार दोपहर श्यामनगर इलाके में चार-पांच हथियारबंद गोगामेड़ी के घर में घुसे और उन्होंने उन पर गोलियां चला दीं। पुलिस ने बताया है कि गोली चलाने वाले हमलावरों की पहचान हो गयी है।

रेवंत रेड्डी के तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे

हैदराबाद। तेलंगाना में बीआरएस को हराकर कांग्रेस को शानदार जीत दिलाने वाले अनुमुला रेवंत रेड्डी राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे और 7 दिसंबर (गुरुवार) को शपथ लेंगे। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। तेलंगाना कांग्रेस प्रमुख कुछ मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में राहुल गांधी भी शामिल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क को उपमुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है या उन्हें किसी अच्छे पोर्टफोलियो पर समायोजित किया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि राज्य में कोई रोटेशनल मुख्यमंत्री फॉर्मूला नहीं होगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने तेलंगाना विधायक दल के नए सीएलपी के रूप में रेवंत रेड्डी के साथ जाने का फैसला किया है। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 7 दिसंबर को होगा।

हमारी विदेश नीति में अफ्रीका को उच्च प्राथमिकता-मोदी

नई दिल्ली। केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रुतो भारत के दौरे पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी और केन्या के राष्ट्रपति विलियम सामोई रुतो की मौजूदगी में भारत और केन्या के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने अपनी विदेश नीति में अफ्रीका को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले लगभग एक दशक में अफ्रीका के साथ अपने संबंधों का मिशन मोड पर विस्तार किया है। उन्होंने कहा कि केन्या के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से न केवल द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे बल्कि अफ्रीका के साथ हमारे जुड़ाव को नई गति मिलेगी।

मोदी ने केन्या के राष्ट्रपति के साथ बातचीत के बाद कहा कि हम भारत-केन्या आर्थिक संबंधों की पूरी क्षमता का पता लगाने के लिए नए अवसर तलाशना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने केन्या के कृषि क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए 25 करोड़ अमेरिकी डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। मोदी ने कहा कि हिंद-प्रशांत में भारत और केन्या के बीच निकट सहयोग साझा प्रयासों को आगे बढ़ाएगा।

गठबंधन को मिला महबूबा और उमर अब्दुल्ला का साथ

जम्मू। विपक्षी गठबंधन इंडिया में हो रही

उठापटक के बीच कांग्रेस को जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी का साथ मिला है। जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि थोड़ी बहुत नाराजगी तो हर जगह चलती रहती है वहीं नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनावों के मुद्दे अलग होते हैं इसलिए भाजपा की जीत को 2024 के लोकसभा चुनावों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए।

महबूबा मुफ्ती के बयान की जहां तक बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने ममता बनर्जी की कांग्रेस से नाराजगी की खबरों पर कहा है कि थोड़ी बहुत नाराजगी कोई मायने नहीं रखती। हम सब बड़े उद्देश्य को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। हम सबको मिलकर उसे बचाना है। दूसरी ओर, उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोकसभा चुनावों में अलग मुद्दे होते हैं इसलिए देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव भी विधानसभा चुनावों की तर्ज पर होते हैं।

आंध्र प्रदेश के बापटला तट से टकराया चक्रवाती तूफान

चेन्नई। गंभीर चक्रवाती तूफान मिगजॉम 90-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ बापटला जिले के करीब आंध्र प्रदेश तट को पार कर गया। वहीं, चेन्नई और उसके आसपास बारिश से संबंधित विभिन्न घटनाओं में अब तक कम से कम 12 लोगों की जान चली गई है, क्योंकि चक्रवाती तूफान मिचौंग के कारण सोमवार को शहर और आसपास के जिलों में लगातार बारिश हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) का कहना है कि चक्रवात मिचुआंग की भूस्खलन प्रक्रिया पूरी हो गई है। चेन्नई के पश्चिम ताम्बरम के बाढ़ग्रस्त कृष्णा नगर इलाके में रहने वाले लोगों को फुली हुई नावों का उपयोग करके बचाया जा रहा है। पुलिस, स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवकों द्वारा बचाव प्रयास जारी हैं।

अधिकारी ने कहा कि लकड़ी एवं पोल कटर से लैस और नौकाओं के साथ बचाव दल पहले से ही तमिलनाडु के विभिन्न हिस्सों में मार्ग-साफ करने का काम कर रहे हैं, जहां मंगलवार सुबह चक्रवात ने कहर बरपाया था। एनडीआरएफ के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि कुछ अतिरिक्त टीम को तैयार रखा गया है और राज्य सरकारों द्वारा मांग किए जाने पर उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में भेजा जाएगा। बापटला जिले के पुलिस अधीक्षक (एसपी) वकुल जिंदल ने बताया कि क्षेत्र में कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है।

सरगुजा संभाग में भाजपा का क्लीन स्वीप, 14-0 का बना इतिहास

छत्तीसगढ़ में भूपेश के भरोसे पर, मोदी की गारंटी भारी पड़ गई !!

संतोष दास 'सरल'

03 दिसम्बर को चार राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद पूरे देश की राजनीति में एकदम से परिवर्तन आ गया है। मध्यप्रदेश, राजस्थान तथा छत्तीसगढ़ में भारी बहुमत में आने के बाद जहाँ भाजपा जीत के जश्न में झूम रही है वहीं एकमात्र तेलंगाना राज्य में ऐतिहासिक जीत के बाद भी कॉंग्रेस खेमे में मायूसी है। तेलंगाना को छोड़ दें तो बाकी तीनों राज्यों के मीडिया व एजेंसियों के एक्जिट पोल फेल साबित हुए हैं। सबसे ज्यादा जिस राज्य के चुनाव परिणाम ने चौंकाया वो है 90 सीटों वाला स्टेट छत्तीसगढ़। चुनाव पूर्व किसी भी एक्जिट पोल ने यहां भाजपा की सरकार बनते नहीं दिखाया था फिर भी 54 सीटों के रिकॉर्ड जीत के साथ भाजपा बहुमत से 09 सीटें ज्यादा जीतकर सरकार बनाने जा रही है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सटीक अनुमान लगाने में माहिर चुनावी विशेषज्ञ प्रेस मीडिया भी जनता की नब्ज़ या कहें अंडर करेंट को पकड़ नहीं पाई। याद करिए आचार संहिता लगने के दो महीने पहले की स्थिति जब 16 अगस्त को भाजपा ने अपने 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी तब भी कोई सर्वे एजेंसी बीजेपी को 30 से ज्यादा सीटें देने को तैयार नहीं थी। लगभग तीन महीने बाद ही भाजपा ने अनुमान से 24-25 सीटें ज्यादा जीतकर न केवल इतिहास रचा बल्कि चुनावी पंडितों के सारे गणित भी फेल कर दिए। विशेष रूप से सरगुजा संभाग की बात करें तो 14 में पूरी 14 सीटें जीतने का अनुमान तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी किसी सपने के सच होने जैसा ही है। इतिहास बताता है कि छत्तीसगढ़ में सरकारें अब तक आदिवासी बहुल सरगुजा तथा बस्तर संभाग के एकतरफ़ा प्रदर्शन से ही बनी है, पिछली बार भी कॉंग्रेस के 14-0 वाले प्रदर्शन से न केवल प्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार बनी बल्कि संभाग का नेतृत्व करने वाले कॉंग्रेस के बड़े नेता टी एस सिंह देव का कद भी बढ़ा। ये अलग बात है कि कॉंग्रेस आलाकमान ने आखिरी समय में उपमुख्यमंत्री बनाकर उन्हें संतुष्ट करने की असफल कोशिश की। सरगुजा अंचल में आए इस ऐतिहासिक परिणाम के कई मायने हैं। टिकट वितरण में एक ओर जहां भाजपा ने रामविचार नेताम, रेणुका सिंह, विष्णुदेव साय, भैयालाल राजवाडे, गोमती साय, श्याम बिहारी जायसवाल जैसे बड़े चेहरों को मैदान में उतारकर बड़ा दांव लगाया तो वहीं प्रबोध मिंज, रामकुमार टोप्पो, राजेश अग्रवाल, भुलन सिंह मरावी, उद्धेश्वरी पैकरा, लक्ष्मी राजवाडे, शकुंतला पोर्ते, रायमुनि भगत जैसे नए चेहरों को मौका देकर जनता को बदलाव का स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की। कॉंग्रेस पार्टी की बात करें तो संभाग में मंत्री प्रेमसाय सिंह और विधायक वृहस्पति सिंह, चिंतामणी महाराज तथा विनय जायसवाल का टिकट काटकर उपमुख्यमंत्री टी एस सिंह देव ने अपने व कॉंग्रेस के लिए मुसीबत ही मोल लिया। टिकट कटने वालों में किसी ने खुले रूप से तो किसी ने अंदर ही अंदर कॉंग्रेस को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। सामरी विधायक चिंतामणी महाराज तो कॉंग्रेस से नाराज होकर बीजेपी में ही आ गये जिसका फायदा प्रत्यक्ष रूप से भाजपा को मिला। आदिवासी अंचल सरगुजा संभाग में भाजपा के क्लीन स्वीप का एक प्रमुख कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दतिमा की ऐतिहासिक सभा में दिया गया उनका वो भाषण भी था जिसमें वो छाती ठोंककर जनता से कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, यानि हर गारंटी पूरी होने की गारंटी। सही कहें तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चुनावी क्रिकेट के आखिरी ओवर में आकर छक्कों चौकों की ऐसी बरसात कर दी जिसका जवाब कॉंग्रेस के पास बिल्कुल नहीं था। उन्होंने जनता के मन में भाजपा के प्रति एक विश्वास का माहौल पैदा किया। भाजपा की जीत का दूसरा सबसे प्रमुख कारण था बड़ी संख्या में महिला वोटरों का घर से निकलकर वोट करना। इस बार बीजेपी की जीत में इन्हीं महिला वोटरों की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही है। चुनाव में बीजेपी की महत्वपूर्ण घोषणा महतारी वंदन योजना का व्यापक असर महिलाओं में देखने को मिला। इस चुनाव में भाजपा की रणनीति कॉंग्रेस से कहीं बेहतर नज़र आई। भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरगुजा सहित पूरे छत्तीसगढ़ में आक्रामक प्रचार किया। चुनाव के दौरान हुए कैंपेन पर नज़र डालें तो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा कॉंग्रेस की ओर से राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में ताबड़तोड़ रैलियां कीं परंतु इन रैलियों में बड़ी संख्या में उमड़ी भीड़ के मामले में तुलनात्मक रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बाजी मारते दिखे। इस चुनाव में आदिवासी वोटरों ने भी भाजपा को जिताने में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। बस्तर और सरगुजा संभाग में पिछले विधानसभा चुनाव में जो आदिवासी समाज बीजेपी से दूर हो गया था वह पुनः भाजपा की ओर लौटता दिखाई दे रहा है। उल्लेखनीय है कि 2003 और 2008 में छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनाने में आदिवासी वर्ग के वोटरों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। यदि पिछले डेढ़ दो सालों के राजनीतिक घटनाक्रमों पर नजर डालें तो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ने आदिवासी वर्ग के हित में कई बड़े निर्णय लिए हैं जिसमें छत्तीसगढ़ की 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करना, आदिवासी गौरव भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को विश्व आदिवासी दिवस की मान्यता देकर छुट्टी घोषित करना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करना तथा आदिवासी वर्ग को सीधे लाभ देने वाली कई

महेश गागड़ा ने बीजापुर की जनता के जनादेश का अपमान किया है: मंडावी

बीजापुर। जिलेके नवनिर्वाचित विधायक विक्रम मंडावी ने पूर्व विधायक महेश गागड़ा के बयान पर कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते है, चुनावों के दौरान जनता अपनी मनपसंद से आगामी पांच वर्षों के लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, इसी प्रक्रिया के तहत बीजापुर की जनता ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी पर अपना भरोसा जताते हुए लोकतांत्रिक रूप से मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना है। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक महेश गागड़ा का अपने प्रेसवार्ता में चुनाव को लेकर दिया गया बयान बीजापुर के मतदाताओं द्वारा कांग्रेस को मिले जनादेश का अपमान है।

विक्रम मंडावी ने मंगलवार को पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व विधायक और भाजपा प्रत्याशी रहे महेश गागड़ा लगातार दो बार चुनाव हार चुके है, अपनी हार से बौखलाकर बीजापुर में शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए चुनावों पर उलजुलूल बयानबाजी कर बीजापुर जिले के मतदाताओं का अपमान करने में लगे है। उन्होने कहा कि वर्ष 2008 और 2013 में वे भी विधायक निर्वाचित हुए थे और भाजपा की सरकार भी बनी थी वे मंत्री भी बन गये तो क्या पूर्व विधायक महेश गागड़ा को उस समय के जिले के कलेक्टर और एसपी ने उन्हें चुनाव जिताया था या फिर बीजापुर जिले की जनता ने चुनाव जिताया था, उन्हें इस बात का खुलासा करना चाहिए।

विक्रम मंडावी ने कहा कि पूर्व विधायक महेश गागड़ा ने बीजापुर की जनता के जनादेश का अपमान किया है, इसलिए पूर्व विधायक महेश गागड़ा को बीजापुर की जनता से माफी मांगनी चाहिए। विक्रम मंडावी ने कहा कि पूर्व विधायक महेश गागड़ा झूठे आरोप लगाने में माहिर है और अब भी वे झूठे आरोप लगाकर जिले के अधिकारी, कर्मचारी और ठेकेदारों को डरा धमकाकर जिले में भय का माहौल बनाने का काम कर रहे है, और अपने आप को आज भी मंत्री समझ रहे है। उन्होने पूर्व विधायक महेश गागड़ा को चुनौती देते हुए कहा कि अब प्रदेश में भाजपा की सरकार है, यदि विक्रम मंडावी ने भ्रष्टाचार किया है तो निष्पक्ष जांच करायें और जेल में डालें। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष लालू राठौर, जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुडियम, जिला पंचायत सदस्या नीना रावतिया उद्दे, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश कारम, सांसद प्रतिनिधि वेणुगोपाल राव सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे।

नक्सल प्रभावित और घनघोर जंगल में सीआरपीएफ बन रही मानवता की मिसाल

बीजापुर। देश का सबसे बड़ा केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, न केवल आतंकियों व नक्सलियों से लोहा लेता है, बल्कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने और निष्पक्ष चुनाव कराने में भी अहम भूमिका अदा करता है। इसके परे भी इस बल की एक खासियत है। वह है बल का सिविक एक्शन प्रोग्राम। इसके तहत सीआरपीएफ, नक्सल प्रभावित इलाकों और घनघोर जंगलों में लोगों की कई तरीके से मदद करती है। बीमार लोगों का इलाज कराती है। कई जगहों पर बच्चों की पढ़ाई-लिखाई और उनकी दिनचर्या से जुड़ी कई मुश्किल राहों को सुगम बनाती है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत एफओबी चिन्नगेलूर में सीआरपीएफ ने मानवता की एक मिसाल कायम की है।

सीआरपीएफ ने नक्सल प्रभावित इलाके बीजापुर के तर्रेम थाना क्षेत्र के अंतर्गत फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस एफओबी चिन्नगेलूर, स्थापित किया था। इस बेस पर सीआरपीएफ की 153वीं बटालियन तैनात है। नक्सलियों को खदड़ने के अलावा, बल के जवान यहां पर कई तरह से लोगों की मदद करते हैं। तीन दिसंबर को छत्तीसगढ़ में वोटों की गिनती चल रही थी। अत्यंत संवेदनशील, नक्सल प्रभावित व घनघोर जंगलों में सीआरपीएफ के जवान ग्रामीण लोगों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वोटों की गिनती के बीच 153वीं बटालियन को यह सूचना मिली कि निकटवर्ती गांव बडा तर्रेम (नदी पारा) में एक महिला, गंभीर तौर पर बीमार है, उसे इलाज नहीं मिल पा रहा है। कमांडर वैद्य संकेत के नेतृत्व में एक टीम गांव के लिए रवाना हो गई। वहां तक एंबुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। इसके चलते जवानों ने एक चारपाई को उल्टा कर स्ट्रेचर बनाया। चूंकि उस जगह पर नक्सलियों के हमले का खतरा बना रहता है। नक्सलियों द्वारा घात लगाकर हमला करना या आईईडी के जरिए सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाना, ऐसी गुंजाइश सदा बनी रहती है। जवानों द्वारा अत्यंत गंभीर हालत में कमली हेमला पत्नी विज्जा हेमला को सीआरपीएफ कैंप तक लाया गया। कैंप कमांडर योगेश के मार्गदर्शन में, 108 नंबर एंबुलेंस सेवा को कॉल किया गया। आधा दर्जन से अधिक जवानों ने चारपाई के स्ट्रेचर को लेकर करीब तीन किलोमीटर का सफर तय किया। प्राथमिक चिकित्सा मुहैया कराने के बाद महिला को एंबुलेंस के जरिए बासागुड़ा रवाना किया गया। कमांडेंट 153 बटालियन राजीव कुमार के मुताबिक, महिला की हालत स्थिर है। उसका इलाज चल रहा है। सीआरपीएफ को कहीं से भी ऐसी कोई सूचना मिलती है, तो वहां तुरंत बल की टीम को रवाना किया जाता है। ग्रामीणों को हर संभव मदद प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता को सीआरपीएफ दोहराती रहती है।

छत्तीसगढ़ भाजपा के जीते हुए सदस्यों को पार्टी का ज्ञान

पहले दिन से प्रदेश के विकास के लिए करें काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा शुरू से ही अपने जीते हुए सदस्यों को रीचार्ज कर रही है। सोमवार शाम कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सभी नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों को छत्तीसगढ़ के विकास के लिए काम करने को कहा गया।

भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी ओम माथुर और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ बात की। माथुर ने विधायकों से कहा कि शपथ ग्रहण के पहले दिन से ही छत्तीसगढ़ की समृद्धि के लिए काम करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि वे राज्य के विकास और लोगों के कल्याण के लिए काम करेंगे। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए पार्टी के सह-प्रभारी मंडाविया ने कहा कि सभी नवनिर्वाचित सदस्यों पर प्रदेश की जनता ने जो भरोसा जताया है उस पर उन्हें खरा उतरना होगा। इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद अरुण साव, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और राज्य के पार्टी सह प्रभारी नितिन नबीन भी उपस्थित रहे।भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी विधानसभा सीट से जीत हासिल करने वाले अरुण साव ने कहा कि जनता ने उन्हें छत्तीसगढ़ को भय और आतंक से मुक्ति दिलाने और राज्य के विकास के लिए काम करने के लिए जनादेश दिया है। उन्होंने कहा, हम सभी इस जनादेश को सलाम करते हैं। हमें लगातार आगे बढ़ना है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में 90 सीटों में 54 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 35 सीटें मिली। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में 1 सीट गई। भाजपा जल्द ही अपने सीएम नाम की घोषणा कर सकती है। सीएम रेस में तीन नाम सबसे आगे हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और रायगढ़ से जीते भाजपा नेता और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी शामिल हैं। देखना होगा भाजपा किसे छत्तीसगढ़ का सीएम बनाती है।

समूह की महिलाओं को लखपति दीदी योजना से जोडने के लिए की गई बैठक

जगदलपुर। महिलाओं को स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसमें से एक है लखपति दीदी योजना। सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से जुड़ी महिलाएं इस योजनाए के तहत अपना काम कर न केवल खुद आत्मनिर्भर हो रही है बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार मुहैया करवाने की दिशा में काम कर रही हैं।

बस्तर जिले के बकावंड विकासखंड को योजना क्रियान्वयन हेतु चिन्हांकित किया गया है इसके लिए बकावण्ड ब्लॉक में सीईओ जनपद एसएस. मंडावी के अध्यक्षता में मंगलवार को महिला लखपति पहल के अंतर्गत मासिक ब्लॉक स्तरीय समन्वय समिति (बीएलसीसी) की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में बिहान, मनरेगा, स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा, कृषि, पंचायत, महिला बाल विकास, मत्स्य पालन विभाग, उद्यानिकी विकास, टीआरआईएफ बकावण्ड टीम और अन्य सभी लाइन डिपार्टमेंट के सदस्य उपस्थित थे।

बैठक के दौरान आने वाले जन योजना अभियान अंतर्गत जीपीडीपी और वीपीआरपी प्रक्रिया के सफल क्रियान्वयन पर चर्चा हुई, साथ ही वीपीआरपी में आईएनआरएम एकीकृत प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संबंधित मांगों का प्रस्तुतीकरण भी किया गया। ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य, पानी अन्य संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। विभागों के जीपीडीपी एवं वीपीआरपी प्रक्रिया में सक्रिय सहयोग प्रदान करने एवं नियमित बैठक के द्वारा सफल संपादन की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए बैठक का समापन हुआ।

साढ़े 8 हजार से अधिक स्कूली बच्चों को जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र

जगदलपुर। कलेक्टर विजय दयाराम के निर्देशानुसार जिले में संचालित स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान से बेहतर उपलब्धि हासिल हुई है, जिससे शैक्षणिक सत्र 2023-24 के तहत अब तक साढ़े 08 हजार से अधिक स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। जिले में स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय के लिए राजस्व, स्कूल शिक्षा और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा समन्वय स्थापित कर इस अभियान को सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है।

कलेक्टर के निर्देश पर जिले के स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय के लिए इस वर्ष 8875 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके एवज में 8875 फार्म प्रतिपूरित कर जांच किया गया और अब तक 8854 फॉर्म ऑनलाइन अपलोड कर जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। जिसमें अब तक 8711 स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया जा चुका है। जिसके तहत बकावंड विकासखण्ड में 1390,बास्तानार में 1079,बस्तर में 2217,दरभा में 651,जगदलपुर में 922,लोहण्डीगुड़ा में 1270 और तोकापाल विकासखण्ड में 1182 स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

जिले में स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय अभियान के अंतर्गत स्कूल स्तर पर स्कूली बच्चों के फार्म प्रतिपूरित कराया जाता है और आवश्यक दस्तावेजों केसाथ सलंग्न कर तहसील कार्यालय में जमा किये जाते हैं। तहसील कार्यालय में उक्त फार्म को ऑनलाइन अपलोड कर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय की कार्यवाही पूरी की जाती है। जिसमें प्रधान अध्यापक, पटवारी, पंचायत सचिव एक साथ मिलकर कार्य को सम्पादित करते हैं और ब्लॉक स्तर पर तहसीलदार एवं खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा समन्वय स्थापित कर जाति प्रमाण पत्र प्रदाय प्रक्रिया पूरी की जाती है। जिले में स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय प्रगति की नियमित तौर पर समीक्षा के फलस्वरूप यह आशातीत उपलब्धि हासिल हुई है। यही वजह है कि विगत शैक्षणिक सत्र के दौरान भी निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप स्कूली बच्चों को जाति प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया था।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सलियों का तांडव, घर का सामान और मवेशी भी ले गये

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में लंबे समय बाद नक्सल मूवमेंट दिखाई दिया है। जिले के चिल्फी थाना क्षेत्र के तहत एक गांव में देर रात नक्सली पहुंचे और एक ग्रामीण के साथ मारपीट कर उसके घर में लूटपाट करने के साथ ही उसके मवेशी भी ले गये। पीड़ित ने चिल्पी थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है। प्रार्थी ने अपने आवेदन में बताया है कि 30 नवंबर को रात में नक्सली राकेश ओढी, समर, जरिना और 10 से 11 सशस्त्र वर्दीधारी महिला-पुरुष नक्सली घर आ गए। माता-पिता की उपस्थिति में गाली गलौज करते हुए मुखबिरी का आरोप लगाकर जमकर मारपीट की। मारपीट के बाद जान से मारने की धमकी देते हुए घर में लूटपाट की और मवेशी भी अपने साथ ले गये। पीड़ित ने बताया कि अपने परिवार से सलाह मशवरा कर सोमवार को रिपोर्ट दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है।

एसपी ने प्रशिक्षु डीएसपी समेत थाना प्रभारियों के प्रभार बदले

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से पुलिस अधिकारियों के पद प्रभार में फेर बदल किया है। जिसमे संगम राम प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक को थाना प्रभारी बिर्रा से बदलकर नैला चौकी उप थाने का प्रभारी बनाया है। निरीक्षक मणीकांत पाण्डेय को यातायात शाखा से थाना प्रभारी बम्हनीडीह का प्रभार दिया गया है। निरीक्षक सुरेन्द्र बघेल को रक्षित केंद्र जांजगीर से यातायात शाखा प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक सत्यम चौहान नैला चौकी प्रभारी को सारागांव थाने का प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक कृष्णपाल सिंह को थाना बिर्रा से थाना बिर्रा का प्रभारी बनाया गया है। उप निरीक्षक लालन पटेल को अकलतरा थाने से यातायात शाखा में भेजा गया है। स.उ.नि. राम प्रसाद बघेल को थाना चांपा से रक्षित केंद्र जांजगीर भेजा गया है। स.उ.नि. दाउ राम बरेठ को थाना सारागांव से रक्षित केंद्र जांजगीर भेजा गया है।

एसईसीएल क्वाटर में छज्जा गिरने से मचा हड़कप

कोरबा। एसईसीएल दीपका के गेवरा कॉलोनी में क्वाटर का एक बड़ा हिस्से का छज्जा गिरने से हड़कप मच गया। इस हादसे में एक परिवार बाल-बाल बच गया। हादसे के बाद एसईसीएल कर्मियों में भारी आक्रोश है। घटना की सूचना पर एसईसीएल के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घटनाक्रम की जानकारी ली। दीपका गेवरा कॉलोनी के एमडी 565 क्वाटर में एसईसीएल कर्मी खगेंद्र प्रसाद नायक निवासी हैं। गेवरा परियोजना में सीनियर सर्वेयर के पद पर हैं। सोमवार की शाम ड्यूटी कर घर पहुंचे ही थे कि अचानक क्वार्टर का सामने वाला एक बड़ा हिस्सा भर भराकर गिर गया। इस हादसे के बाद हड़कप मच गया। आसपास कॉलोनी वालों ने इसकी आवाज सुनी तो दौड़े चले आए। खगेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस घटना में घर के आंगन में दो मासूम बच्चे खेल रहे थे, जो बाल-बाल बच गए। नहीं तो कोई बड़ा हादसा हो सकता था। खगेंद्र प्रसाद ने आरोप लगाया कि एसईसीएल के मेंटेनेंस विभाग में बार-बार शिकायत किए जाने के बावजूद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया।

चक्रवाती तूफान मिचौंग ने बदला छत्तीसगढ़ का मिजाज

कोरबा। कोरबा में चक्रवाती तुफान मिचौंग के कारण पूरे देश के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। आंध्रप्रदेश और तमिलनाडू में भारी बारिश होने के कारण कई लोगों की मौत भी हुई है। वहीं छत्तीसगढ़ में हल्की बारिश होने के कारण मौसम पूरी तरह से बदल गया है। बारिश के चलते ठंड बढ़ने से लोग अब अलाव का सहारा लेने लगे हैं। चक्रवाती तुफान मिचौंग के कारण दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में जमकर तबाही मची है। आंध्रप्रदेश और तमिलनाडू में भारी बारिश होने के साथ ही जलजमाव की स्थिती बनी हुई है, वहीं कई लोगों की मौत की खबर भी है। मिचौंग का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है, जहां सभी जिलों का मौसम पूरी तरह से बदल गया है।आसमान में बादल छाने के साथ ही सुबह से ही बारिश हो रही है जिसके कारण मौसम काफी ठंडा हो गया है। अचानक बढ़ी ढंग से निजात पाने के लिए लोग अब अलाव का सहारा लेने लगे हैं। आगामी कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज इसी तरह के बने रहने का अनुमान लगाया जा रहा है।

चक्रवाती तूफान मिचौंग से छत्तीसगढ़ में कई ट्रेनें रद्द

बिलासपुर। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में मिचौंग तूफान के चलते ऐहतियातन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से चलने और यहां से गुजरने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। शादी के सीजन में ट्रेनों के रद्द होने से जहां यात्रियों को असुविधा होगी वही इस तूफान से हवाई सेवा भी प्रभावित हो सकती है। मिचौंग तूफान की वजह से बिलासपुर में सोमवार देर रात से बारिश शुरू हो गई और बारिश की वजह से कई इलाकों की बिजली पूरे रात बंद रही है। इसके साथ ही दोपहर तक बारिश लगातार गिरने की वजह से शहर के कुछ निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है, जिसे देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने व्यवस्था दुरुस्त करने की कवायद शुरू कर दी है। जो गाड़िया 4 दिसंबर को चलकर पांच दिसंबर को दक्षिण पहुंचती उन्हें शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया था ताकि ये गाड़ी अपने गंतव्य के पहले बारिश और तूफान में न फंस जाए या फिर भूस्खलन की वजह से दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए। इसलिए कुछ ट्रेनों को 4 तारीख से ही रद्द कर दिया गया है।

छत्तीसगढ़ की जनता ने चटाया करोड़पतियों को धूल

रायपुर। 2023 में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में कमल खिलाकर प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी की प्रचंड जीत में कई ऐसे नेता भी विधायक बन गए ,जो चुनाव आयोग के आंकड़ों में करोड़पति हैं। सिर्फ जीतने वालों में ही करोड़पति विधायक नहीं हैं, हारने वालों की फेहरिश्त में भी करोड़पति उम्मीदवार थे, जो चुनाव में मुंह के बल गिरे। हारने वाले करोड़पति नेताओं की लिस्ट में पहला नाम टीएस सिंहदेव का है। जीतने वाले करोड़पति नेताओं की लिस्ट में पहला नाम भावना बोहरा का है। कवर्धा से पहली बार चुनाव लड़ने वाले आप के प्रत्याशी खडगराज सिंह भी करोड़पति प्रत्याशी थे जो चुनाव नहीं जीत सके।

छत्तीसगढ़ के सियासी जंग में कई करोड़पति जीत गए, कई करोड़पति हार गए। राजघराने से आने वाले टीएस सिंहदेव सरकार में दूसरे नंबर पर थे, वो चुनाव हार गए। छत्तीसगढ़ इलेक्शन वॉच के मुताबिक साल 2023 में टीएस सिंहदेव ने चुनाव के दौरान अपनी सपंत्ति 447 करोड़ रुपए घोषित की थी। दूसरे सबसे बड़े करोड़पति मनेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रमेश सिंह चुनाव हार गए। तीसरे करोड़पति राजिम से अमितेश शुक्ल कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और हार गए। पंडरिया से चुनाव लड़ रहीं बीजेपी की भावना बोहरा 33 करोड़ की मालकिन हैं। भावना बोहरा बीजेपी के सिंबल पर चुनाव जीत गई हैं। वैशाली नगर से निर्दलीय प्रत्याशी संगीता केतन शाह भी करोड़ों की मालकिन हैं। वो भी चुनाव हार गईं। पाटन से चुनाव जीतने वाले भूपेश बघेल भी करोड़ों के मालिक हैं। नामांकन के दौरान भूपेश बघेल ने संपत्ति का ब्योरा आयोग के सामने दिया था। भूपेश बघेल चुनाव जीत गए। कवर्धा सीट से आप नेता खडगराज सिंह भी 40 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं। चुनाव में वो भी इस बार हार गए। कवर्धा से हारने वाले कांग्रेस के मोहम्मद अकबर भी करोड़ के मालिक हैं। राजनांदगांव से जीतने वाले बीजेपी के रमन सिंह भी करोड़पति हैं। बस्तर से कांग्रेस के लखेश्वर बघेल भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं लेकिन चुनाव में इस बार हार गए। कांग्रेस के इंद्रशाह मंडावी भी करोड़पति उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस की हर्षिता स्वामी बघेल भी करोड़पति उम्मीदवार थीं। जगदलपुर सीट से हारने वाले कांग्रेस के जतीन जायसवाल भी करोड़पति उम्मीदवार थे। चुनाव में जीतने के लिए हर नेता एड़ी चोटी का जोर लगाता है। पैसे भी खर्च करता है। जनता का वोट उसी को मिलता है, जो विकास का काम करता है और जनता को विकास के रास्ते पर ले जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव परिणाम ये बताते हैं कि जनता जिसके साथ है, उसी की जीत हुई। प्रत्याशियों के अमीर और गरीब होने का असर जनता के वोटों पर नहीं पड़ता है।

वापस कांग्रेस का गढ़ बनीं कोटा सीट अटल श्रीवास्तव ने किया कमाल

कोटा। बिलासपुर संभाग का कोटा विधानसभा सीट कांग्रेस का अभेध किला रहा है। यहां काफी अरसे से कांग्रेस का कब्जा रहा। लेकिन साल 2018 के चुनाव में जेसीसीजेने इस सीट पर जीत दर्ज कर कांग्रेस से यह सीट छीन ली। हालांकि कांग्रेस का गढ़ वापस कांग्रेस को मिल गया। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव को जीत मिली है। इस बार अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी के धाकड़ नेता कहे जाने वाले प्रबल प्रताप सिंह जूदेव को हरा दिया। इतना ही नहीं अटल श्रीवास्तव ने इस बार जोगी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेणु जोगी को भी इस सीट से मात दी है। इस सीट पर साल 2018 में रेणु जोगी चुनाव जीती थी।

कोटा सीट पर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही अपने पार्टियों के घोषणा पत्र और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस के उम्मीदवार अटल श्रीवास्तव ने बघेल सरकार की योजनाओं का हवाला दिया। जबकि बीजेपी के उम्मीदवार प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने पीएम मोदी के वादों और देश के विकास की बात कहते हुए वोट मांगे। जबकि जेसीसीजे की तरफ से छत्तीसगढ़ियावाद का नारा बुलंद किया गया।

कोटा सीट पर साल 2018 के चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यहां से जेसीसीजे की प्रत्याशी रेणु जोगी ने बीजेपी के काशी साहू को हराया था।

कोटा सीट को बिलासपुर संभाग का सबसे अहम सीट माना जाता है। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अटल श्रीवास्तव का ऐसा कमाल चला कि उन्हें जीत मिल गई। इस जीत के साथ अटल श्रीवास्तव अब नेता प्रतिपक्ष के दौड़ में शामिल हो गए हैं।

छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन, सस्पेंस बरकरार, कई नामों पर चर्चा

अरुण साव सीएम बनने की रेस में आगे, संघ और शाह की पहली पसंद!

बिलासपुर। 2023 की जंग में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। छत्तीसगढ़ की 90 में से 54 सीटों पर बीजेपी ने कमल खिलाया। जबकि साल 2018 में 68 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 35 सीटों पर ही अपनी छाप छोड़ सकी। बीजेपी को मिली इस बड़ी जीत में कई नेताओं के नाम शामिल हैं। उसमें एक नाम अरुण साव भी हैं। अरुण साव का नाम छत्तीसगढ़ सीएम की रेस में शामिल हैं। सामान्य कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक का सफर करने वाले अरुण साव के बारे में कहा जाता है कि जब उनसे सीएम बनने को लेकर सवाल पूछा जाता है तो वह हंसकर टाल जाते हैं।

देश की राजनीति में जैसे अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य माना जाता है, ठीक उसी तरह से छत्तीसगढ़ की राजनीति का चाणक्य अरुण साव को मानते हैं। 2018 में मिली हार से बीजेपी ने सबक लिया। 2023 की जंग जीतने के लिए बीजेपी ने पांच सालों का लंबा इतंजार और मेहतन की। पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाले अरुण साव ने प्रदेश अध्यक्ष बनते ही पार्टी को एकजुट किया, गुटबाजी पर लगाम लगाया। सीट बंटवारे से लेकर प्रदेश स्तर के नेताओं को प्रचार में झोंकने की रणनीति बनाई। स्थानीय नेताओं को रिचार्ज किया, पुराने कार्यकर्ताओं को जमीन पर लेकर आए। अरुण साव के बारे में कहा जाता है कि वो कई कार्यकर्ता को बाकायदा उनके नाम से जानते हैं। बहुत कम ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होते हैं जो कार्यकर्ताओं को बाकायदा उनके नाम से जानते हैं। कार्यकर्ता को भी जब उनके प्रदेश अध्यक्ष नाम से पुकारें तो उनका हौसला सांतवें आसमान पर पहुंच जाता है। 2023 की लड़ाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं का

जोश आपको नजर आया उसके पीछे भी इसी छत्तीसगढ़ के चाणक्य का हाथ माना जाता है।

अरुण साव संघ की भी पहली पसंद हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आए अरुण साव साल 1990 से साल 1995 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की छात्र राजनीति से जुड़े रहे। संघ के कई पदों पर रहकर बेहतर काम किया। भारतीय जनता पार्टी में आने पर बूथ कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के कार्यक्रमों तक की व्यवस्था करने वाले नेताओं में शुमार रहे। कार्यकर्ता से लेकर सांसद बनने तक का उनका लंबा सफर ये बताने के लिए काफी है कि वो कितने सक्षम हैं। जब वो सांसद बने तो रिकार्ड 1 लाख 41 हजार वोटों से विजयी हुए। सदन के पटल से छत्तीसगढ़ की आवाज भी हमेशा बनते रहे। लोकसभा में जब वो छत्तीसगढ़ के मुद्दों को उठाते थे विपक्ष के सदस्य भी उनको ध्यान से सुनते थे।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी अरुण साव की कार्य क्षमता को देखते हुए पार्टी का अध्यक्ष बनाया फिर चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। 2023 विधानसभा चुनाव की प्रदेश में पूरी जिम्मेदारी अरुण साव के ही कंधे पर थी। वो खुद लोरमी से चुनाव लड़ भी रहे थे और पार्टी के लिए प्रचार के साथ काम भी कर रहे थे। एक साथ तीन तीन मोर्चो पर काम करते हुए बड़ी जीत हासिल करना किसी और के बस की बात नहीं थी। एक सामान्य कार्यकर्ता से लेकर सांसद बनने तक का सफर पूरा करने वाले साव आज भी खुद का कार्यकर्ता ही मानते हैं।

संघ और अमित शाह की पसंद के साथ साथ अरुण साव ओबीसी के खांचे में भी फिट बैठते हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति को करीब से जानने वाले ये मानते हैं कि अगर पार्टी अरुण साव को मौका देती है तो अरुण साव के साथ ओबीसी वोटों पर भी बीजेपी का कब्जा हो जाएगा। 2024 की जंग में अरुण साव और ओबीसी वोटर दोनों बीजेपी के लिए तरुप का इक्का साबित हो सकते हैं। पार्टी आलाकमान जब भी सीएम पद के रेस में आने वाले लोगों की चर्चा करेगा अरुण साव की ये खूबियां सबसे ऊपर होंगी।

अरुण साव का पूरा बचपन बिलासपुर में बीता। पिता स्वर्गीय श्री अभय राम साव किसान थे। अरुण साव की स्कूली शिक्षा बिलासपुर में हुई फिर मुंगेली से बी कॉम की पढ़ाई पूरी की। साव ने आगे की पढ़ाई कौशलेंद्र राव विधि महाविद्यालय से की। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो वकालत के पेश में आए। बहुत कम लोग जानते हैं कि अरुण साव के कुशल अधिवक्ता भी हैं।

बिलासपुर से लेकर रायपुर तक और बस्तर से लेकर दुर्ग तक के कार्यकर्ता अरुण साव को छत्तीसगढ़ के सीएम के पद पर देखना चाहते हैं। ये बीजेपी का अनुशासन ही है कि पार्टी जब भी जिसको भी कमान संभालने का आदेश देती है वो पार्टी के आदेश को माथे से लगा लेता है। पार्टी के आदेश की अवहेलना नहीं करता। इसीलिए बीजेपी के बारे में विरोधी भी कहते हैं बीजेपी मतलब पार्टी विद ए डिफरेंस।

क्या छत्तीसगढ़ की पहली महिला सीएम बनेंगी रेणुका सिंह

रायपुर/ सरगुजा। 2023 का छत्तीसगढ़ चुनाव जीतने के बाद अब छत्तीसगढ़ बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाने की तैयारियां तेज कर दी है। सीएम कौन बनेगा अब ये पार्टी और जनता दोनों के लिए बड़ा सवाल हो गया है। भरतपुर सोनहत से चुनाव जीतकर आने वाली रेणुका सिंह की दमदारी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मोदी के मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिली। टीएस सिंह देव के गढ़ में घुसकर उन्होने कांग्रेस को न सिर्फ चुनौती दी बल्कि सरगुजा की सभी सीटों पर पार्टी को चुनाव भी जितवाया। भरतपुर सोनहत सीट से जिस गुलाब कमरो को रेणुका सिंह ने हराया वो कांग्रेस के मौजूदा विधायक थे।

छत्तीसगढ़ की कद्दावर महिलाओं नेताओं में रेणुका सिंह सबसे आगे हैं। आदिवासी लोगों के बीच इनकी पैठ काफी गहरी है। राजनीति का लंबा अनुभव भी इनके पक्ष में जाता है। जिस तरह से सरगुजा संभाग में रेणुका सिंह ने प्रचार की कमान संभालकर पार्टी को एकतरफा जीत दिलाई वो काबिले तारीफ रहा। पार्टी जब छत्तीसगढ़ के सीएम पद के दावेदारी पर चर्चा करेगी तो रेणुका सिंह का नाम सबसे पहले आएगा। नारी वंदन योजना के पीछे भी इनका ही दिमाग था। कहा जाता है कि पार्टी ने जिस नारी वंदन योजना को चुनाव के दौरान लांच किया उसके पीछे का दिमाग रेणुका सिंह का ही था। रेणुका सिंह ने अपने प्रचार के दौरान पूरे सरगुजा संभाग में नारी वंदन योजना का फायद घर घर पहुंचाया। गोंड समाज पर रेणुका सिंह की पकड़ काफी जोरदार है। सरगुजा संभाग में गोंड समाज की अच्छी खासी संख्या है। लोकसभा चुनावों में अगर बीजेपी को ये रिकार्ड दोहराना है तो रेणुका सिंह उस जीत को सही रास्ता दे सकती हैं। विष्णुदेव साय के बाद रेणुका सिंह ही एक मात्र केंद्रीय राज्य मंत्री रहीं जिनको खुद मोदी ने अपनी कैबिनेट में जगह दिया। जनपद पंचायत से शुरु हुआ उनका लंबा संघर्ष ये बताता है कि वो कितनी बड़ी महिला नेता हैं। 1999 में पहली बार वो जनपद पंचायत के सदस्य के तौर पर चुनीं गईं। पार्टी ने उनका काम और मेहनत को देखते हुए साल 2000 में उनको रामानुजगंज मडंल का बीजेपी अध्यक्ष बनाया। यहां से शुरु आ उनका पार्टी सफर फिर आगे कभी रुका नहीं साल 2008 में दूसरी बार वो विधायक बन गईं। साल 2002 में रेणुका सिंह को समाज कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्ति किया गया। कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनने के बाद रेणुका सिंह ने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे गरीबों का उत्थान हुआ और आदिवासी समाज में उनकी पैठ बढ़ती गई। छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाके से आने वाली रेणुका सिंह के बढ़के कद को पार्टी ने भी स्वीकार किया और साल 2019 में उनका सांसद का टिकट दिया। पार्टी आलाकमान के फैसले पर रेणुका सिंह खरी उतरीं और जीत दर्ज की। केंद्रीय नेतृत्व और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी तारीफ करते हुए उनको कैबिनेट में जगह दी। वर्तमान में रेणुका सिंह जनजातीय मामलों की केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। कोरिया के छोटे से गांव पोडी बच्चा में उनका जन्म 5 जनवरी 1964 को हुआ था। ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई उनकी छत्तीसगढ़ में ही हुई। कॉलेज के जमाने से ही उनको उनके साथ तेज तर्रार नेता की तरह देखते थे, उनके भीतर नेता बनने और नेतृत्व करने का गुण भी देखते थे। रेणुका सिंह का विवाह सूरजपुर जिले में नरेंद्र सिंह के साथ हुआ। रेणुका सिंह की दो बेटियां है जिनका नाम पूर्णिमा सिंह और मोनिका सिंह हैं।

संक्षिप्त समाचार

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्यपाल को सौंपी निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची

रायपुर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले ने मंगलवार को दोपहर राजभवन में राज्यपाल श्री विश्वभूषण हरिचंदन से भेंट कर उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य की छठवीं विधानसभा के गठन के निर्वाचित सदस्यों की अधिसूचना के साथ नव-निर्वाचित अभ्यर्थियों की सूची सौंपी। इस अवसर पर भारत निर्वाचन आयोग के प्रधान सचिव एस बी जोशी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नीलेश महादेव क्षीरसागर, राज्यपाल के सचिव अमृत कुमार खलखो, अवर सचिव रितेश सिंह, सेक्शन अधिकारी देवेश सिंह एवं जूनियर असिस्टेंट श्री अनीश उपस्थित थे।

स्काईवाक की घटना को कांग्रेस का ताबूत बनाकर मैं जनता को समर्पित करूंगा

रायपुर। पूर्व लोक निर्माण मंत्री व वर्तमान में रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आमानाका चौक के पास बने चौपाटी के साथ ही स्काईवाक विवाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई थी और कांग्रेस के लोगों ने उनके राजनीति जीवन में उनके चरित्र की हत्या करने की कोशिश की है। कांग्रेस राज में ना खाता का पता है और ना बही, उन्होंने जो कहा वो सही साबित हुआ। मूणत ने कहा कि स्काईवाक की घटना को कांग्रेस का ताबूत बनाकर मैं जनता को समर्पित करूंगा। कांग्रेस ने पूरे शहर को चौपट कर दिया ही, इसलिए कांग्रेस के हाथ से 7 सीटें चली गयी।

अविश्वास प्रस्ताव लाने भाजपा पार्षद दल की बैठक

रायपुर। सूबे की सत्ता में भाजपा सरकार के काबिज होते ही इसका असर अब स्थानीय निकायों पर दिखाई देने लगा है। इसी कड़ी में मंगलवार को निगम मुख्यालय महात्मा गांधी सदन में भाजपा पार्षदों की बैठक हुई जिसमें पार्षदों ने महापौर एजाज ढेबर से इस्तीफे की मांग की इस्तीफा नहीं देने पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही। बैठक में शामिल होने के बाद भाजपा पार्षद की नेता मीनल चौबे ने कहा कि महापौर नैतिकता के अधार पर इस्तीफा दे। बैठक के बाद भाजपा पार्षद दल ने कहा कि महापौर का इस्तीफा नहीं होने पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा।

हारकर मैदान नहीं छोड़ूंगा : टीएस सिंहदेव

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के बाद कोई भी चुनाव ना लड़ने की बात कहने वाले पूर्व डिप्टी सीएम अपनी ही बात से पलट गए हैं। सिंहदेव ने कहा कि जीत जाता तो विरासत सौंप देता लेकिन हारने के बाद मैदान नहीं छोड़ूंगा।

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के बाद टीएस सिंहदेव ने घोषणा की थी कि यह उनका आखरी चुनाव है। चुनाव जीतने के बाद वह अगले 5 साल तक जनता की सेवा करेंगे और उसके बाद विरासत अगली पीढ़ी को सौंप देंगे लेकिन इस चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दरअसल टीएस सिंहदेव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे। लेकिन काफी कम अंतर से वे चुनाव हार गए।लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे विधानसभा में ही रहना पसंद करेंगे। टीएस सिंहदेव ने कहा मैंने इस बात को ध्यान में रखकर कहा था कि चुनाव जीतूंगा और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों को जिम्मेदारी सौंपूंगा।

अंबिकापुर विधानसभा से कुल 13 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा।

कांग्रेस से टीएस सिंहदेव को 90686 वोट, भाजपा से राजेश अग्रवाल को 90780 वोट मिले। यहां 21 वें और आखिरी राउंड और पोस्टल वैलेट की गिनती के बाद डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव 137 वोट से चुनाव हार गये। इसकी रीकाउंटिंग की गई लेकिन उसमें भी टीएस सिंहदेव को जीत नहीं मिली। वह 94 वोटों से राजेश अग्रवाल से चुनाव हार गए। टीएस सिंहदेव ने कहा मैं हार कर मैदान नहीं छोड़ूंगा। हारा हूं तो अगले पांच साल पूरा प्रयास करुंगा और क्षेत्र में लोगों से संपर्क बनाकर रखूंगा। अंबिकापुर की जनता के लिए जो भी पहल कर सकता हूं मैं करुंगा।

छत्तीसगढ़ में भाजपा को मिले पूर्ण बहुमत व संभाग में कांग्रेस को 14 सीटें गवाने को लेकर सिंहदेव ने भाजपा को जीत की बधाई देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार ने भी अच्छे काम किया है और विश्वास करुंगा कि उन कामों में निरंतरता बनी रहे और अच्छे काम सरगुजा व छत्तीसगढ़ के हित में होते रहे। हार जीत के कई कारण होते है लेकिन सरगुजा संभाग में पिछली कांग्रेस के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम आया था और इस बार ठीक उलट व अकल्पनीय रूप से 14 सीटों को भाजपा जीती है। चुनाव में हुए उलटफेर को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट शेयर घटा नहीं है लेकिन भाजपा का वोट शेयर 14 प्रतिशत बढ़ गया है।

अरूण साव को दिल्ली बुलावा

रायपुर/दिल्ली। चुनाव जीतने के बाद छत्तीसगढ में सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई और मुख्यमंत्री को लेकर भी अटकलों का दौर चल रहा है और छत्तीसगढ के सिंहासन पर में किसकी ताजपोशी होगी इस पर फिलहाल कुहासा है। लेकिन इसी बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बुलावे पर दिल्ली रवाना हो गये जहां पार्टी की हो रही अहम बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ये बैठक बुलाई है। वहीं, छत्तीसगढ़ विधायकों से मुलाकात कर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मानसुख मांडविया और सह प्रभारी नितिन नबीन दिल्ली लौटे चुके हैं। वहीं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है, कि वे इस बैठक में शामिल हो सकते हैं।

अभी एक चौथाई शताब्दी तक राहुल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है: अजय चंद्राकर

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी ने ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया है। विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब बीजेपी प्रदेश कार्यलय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में नई सरकार के गठन कती कवायद तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ भाजपा के बड़े नेता और रमन सिंह सरकार रके पूर्व मंत्री रहे अजय चंद्राकर ने इस जीत में मोदी की गारंटी को गेमचेंजर बताया है। साथ ही उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है।

पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा, मोदी जी की जितनी गारंटी थी, सब गेमचेंजर है। युवा, महिला, गरीब और किसान यही तो समाज है। इसी से मिलकर समाज बनता है और समाज पर ही भरोसा उन्होंने जताया है। हम छत्तीसगढ़ की जनता, देश की जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं। उनके मार्गदर्शन में, उनके गारंटी से छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व

जीत मिली, ऐतिहासिक बहुमत मिला। मोदी जी की गारंटी ही जीत की वजह है, उनके जैसा विश्वसनीय नेता हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व में नहीं है।

छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री को लेकर अजय चंद्राकर ने कहा, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारे ऊपर के लीडरशिप फैसला करेगी। आप ऊपर के हमारे नेताओं से पूछिए।

अजय चंद्राकर ने आगे कहा, मेरे ट्वीट को आप लोग यदि पढ़ रहे होंगे तो आप देखेंगे मैं तो शुरु से ही आश्वस्त था। सिंहासन खाली करो, आप कितने दिन में सीएम हाउस खाली करेंगे, कांग्रेस कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, इस्तीफा देने के समय के लिए विचार किया जा रहा है। इस प्रकार के मेरे लेखन देखेंगे तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पर हमेशा से ही आश्वस्त था।

अजय चंद्राकर ने कहा बघेल के हाथ में कुछ भी नहीं था और उन्होंने पांच सालों में बड़ा नाम कमाया। यह उसी का परिणाम है। उन्होंने छत्तीसगढ़ को ऐसे क्षेत्रों में आगे बढ़ाया, जिसके बारे में हमारे पुरखे भी नहीं सोंचते थे। उन्होंने जूआ, सट्टा, चोरी, लेवी वसूली इन क्षेत्रों में नाम कमाया।

2024 के सवाल पर अजय चंद्राकर ने कहा, इसमें कोई संदेह है क्या? आपको, मोदी की तीसरी बार ताजपोशी होगी। अभी एक चौथाई शताब्दी तक राहुल के लिए कोई वैकेंसी नहीं है।

आप-जकांछ से ज्यादा 19 विधानसभा सीटों में तीसरे नम्बर पर रहा नोटा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आए चुनाव परिणाम ने राजनीति के जानकारों को भी चौंका दिया था जिसमें सबसे चौंकाने वाली एक बात यह भी है कि प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और बसपा को छोड़कर नोटा को सबसे अधिक वोट मिले हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त आम आदमी पार्टी को 0.93 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को 1.23 फीसदी ही वोट मिले जबकि नोटा को 1.26 फीसदी वोट मिले हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अन्य को मिलाकर 12 राजनीतिक दलों के वोटों का प्रतिशत जारी की है इसमें नोटा 4 नंबर पर है।

इस बार आम आदमी पार्टी और जकांछ दोनों ने सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतरे हैं। एक वजह यह है कि भी दोनों राजनीतिक दलों को वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। इस बार भी आम आदमी पार्टी और जकांछ दोनों किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत सकी है। जबकि पिछली बार जकांछ और बसपा ने गठबंधन किया था उनका प्रदर्शन भी शानदार था। इस बार आप और जकांछ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कुछ ही सीटों पर दोनों दल के प्रत्याशी तीसरे नम्बर पर आएं। बता दें कि वर्ष 2013 और 2018 के मुकाबले नोटा को कम वोट मिले हैं। नोटा को सबसे ज्यादा 8620 वोट दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में मिले हैं। चित्रकोट विधानसभा सीट में भी नोटा को 7310 वोट मिले थे। यहां पर कांग्रेस-भाजपा के प्रत्याशियों के बाद नोटा तीसरे नम्बर पर था।

हर चुनाव की तरह इस चुनाव में भी नोटा ने प्रत्याशियों के हार-जीत का गणित बिगड़ाने में कामयाब रहा है। तीन विधानसभा सीट ऐसी है, जहां हार-जीत के अंतर से ज्यादा वोट नोटा को मिला। इसमें बीजापुर, बिंद्रानवागढ़ और धमतरी विधानसभा की सीट शामिल हैं। बीजापुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विक्रम मंडावी ने भाजपा प्रत्याशी महेश गागड़ा को हराया है। मंडावी को 2706 वोटों से जीत मिली थी। जबकि नोटो को 3628 वोट मिले थे। इसी तरह धमतरी में कांग्रेस के ओंकार साहू ने भाजपा की रंजना डीपेन्द्र साहू को 2606 वोटों से पराजित किया है। जबकि यहां नोटा को 2695 वोट मिले हैं। बिन्द्रानवागढ़ में कांग्रेस के जनक राम ध्रुव ने भाजपा के गोवर्धन मांझी को 816 मतों से पराजित किया। यहां नोटा को 3710 मत मिले हैं।

अपना-अपना चलाने के चक्कर में निपट गए सब: अमरजीत

■ **कांग्रेस की हार पर पूर्व मंत्री भगत का बड़ा बयान**

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के 90 विधानसभा सीटों में प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा ने सत्ता में वापसी की है। प्रदेश में भाजपा 54 सीटों में जीती है। वहीं कांग्रेस के खाते में 35 और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के खाते में एक सीट आई है। इस चुनाव में सबसे चौकाने वाले नतीजे सरगुजा संभाग से आए। यहां के 14 सीटों में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत सकी जबकि 2018 के चुनाव में कांग्रेस का पूरे 14 सीटों में कब्जा था।

कांग्रेस की इस बड़ी हार पर पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अपना-अपना चलाने के चक्कर में सब निपट गए। जो जनादेश आया है, उसकी थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी। आपस में सामंजस्य की कमी भी रही, जिसका असर दिखा।

टिकट काटने का फॉर्मूला फ्लाप होने पर अमरजीत भगत ने कहा कि यह फॉर्मूला नहीं चल पाया। इसी के चलते एक दूसरे को निपटाने में यह हुआ। अमरजीत भगत ने गड़बड़ी की भी आशंका जताई है।

टीएस सिंहदेव ने कहा मुझे सीएम नहीं बनाए इस वजह से सभी सीटें हारे। टीएस सिंहदेव के बयान पर अमरजीत भगत ने कहा कि इन बातों में कोई दम नहीं है, पहले सबको साथ लेकर तो चलना था।

बुलडोजर को लेकर अमरजीत भगत ने कहा कि बिना ब्रेक का गाड़ी है। जिसे टारगेट किया है उसे भोगना पड़ेगा। जो उनके एजेंडे में है वह सब करेंगे, सबको संभालना है।

मूंछ मुंडवाने वाले बयान पर फंसे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आने के बाद भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। प्रदेश में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत हर ओर चर्चा है। वहीं सियासी बयानबाजी भी जारी है। इस बीच पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मूंछ मुंडवाने वाले बयान पर बीजेपी उन्हें रेडार में लेने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। अब अमरजीत भगत को केदार कश्यप ने आड़े हाथों लिया है और कहा कि भगत चाहे तो मैं ही उनकी मूंछ मुड़वाने में उनकी मदद करूंगा।

बता दें कि चुनाव से पहले पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के मूंछ मुड़वाने के बयान और उनके वीडियो वायरल होने पर भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि जनता ने उनके गुरुर को तोड़ने का काम किया, उनके दावे खत्म हो गए। अमरजीत भगत मेरे पड़ोसी हैं वे चाहे तो मैं ही उनकी मूंछ मुड़वाने में उनकी मदद करूंगा।

बुलडोजर को लेकर भाजपा नेता केदार कश्यप ने कहा कि भ्रष्टाचार, कुशासन पर बुलडोजर चलेगा। जो गलत करेगा, उस पर बुलडोजर चलेगा। हमारे कार्यकर्ताओ में जोश और जुनून है।

छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री के चेहरे पर केदार कश्यप ने कहा कि उद्देश्य था कि सरकार बने। सभी जगह बेहतर परिणाम और सबका समर्थन प्राप्त हुआ। सबका साथ, सबका विकास यही लेकर चलते हैं। विधायक दल की बैठक के बाद सीएम का फैसला होगा।

बस्तर और सरगुजा की सीट पर मिली बढ़त को लेकर केदार कश्यप ने कहा, कांग्रेस ने 75 पार की बात कही थी। सारे दिग्गज नेता हार गए। पीसीसी चीफ दीपक बैज घमंड के साथ कहते थे मैं केवल फॉर्म भरने जाऊंगा, वोट मिल जायेगा फिर प्रमाण पत्र लूंगा। कांग्रेस ने जनता को टॉलरेट किया। भाजपा के मंडल अध्यक्ष ने उन्हें हराया है।

खुद के सीएम बनने की इच्छा पर केदार कश्यप ने कहा मैंने दावा नहीं किया। भाजपा ने पद प्रतिष्ठा सम्मान दिया है। मुझे विधायक मंत्री प्रदेश में महामंत्री की जिम्मेदारी दी गई। इसे बड़ा दायित्व और क्या हो सकता है।

भूपेश के इस्तीफे के बाद प्रमुख सचिव डॉ. आलोक शुक्ला समेत चार सलाहकारों ने दिया इस्तीफा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के करारी हार के बाद अब प्रदेश कांग्रेस में इस्तीफे का दौरा चल रहा है। चुनाव परिणाम आने के बाद निवर्तमान सीएम भूपेश बघेल ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल को इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद अधिकारियों के भी इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं भूपेश बघेल के चारों सलाहकारों के इस्तीफे के बाद राज्य शासन ने उनकी सेवाएं खत्म कर दिया है। इसके साथ ही उनकी सभी सरकारी सुविधाएं भी वापस ले लिया गया है।

भूपेश बघेल के चार सलाहकारों में राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा, पंचायत और ग्रामीण विकास सलाहकार प्रदीप शर्मा, संसदीय सलाहकार राजेश तिवारी और मीडिया सलाहकार रूचिर गर्ग शामिल हैं। इस्तीफे के बाद मुख्य सचिव ने आगे की कार्रवाई करने के लिए जीएडी को भेज दिया है। वहीं सलाहकारों के भवन को खली करने को कहा है।

महाअधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और संविदा नियुक्ति में प्रमुख सचिव शिक्षा के पद पर सेवा दे रहे पूर्व आईएएस डॉ. आलोक शुक्ला अपना इस्तीफा राज्य शासन को भेज चुके हैं। इसके साथ ही ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी ने भी अपना इस्तीफा विभागीय सचिव को सौंप दिया है।

इसी क्रम में भूपेश बघेल के सचिवालय में पदस्थ अफसरों को मूल विभाग में लौटाने के लिए छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जरी कर दिया है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग ने दो निज सचिव और चार ओएसडी को मूल विभाग वापस भेज दिया है।

तीन राज्यों में छोटे दलों की नहीं गली दाल

अल्पयू सिंह

चार राज्यों के चुनाव नतीजे सामने हैं। इनमें तीन उत्तर भारतीय राज्यों के परिणाम देश की राजनीति में एक नए तरह के बदलाव का संकेत दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि मल्टी पार्टी सिस्टम और खिचड़ी सरकारों के दौर से निकलकर राजनीति अब साफ-साफ टू पार्टी सिस्टम की ओर बढ़ रही है। इन राज्यों में जिस तरह से कांग्रेस के पैरों तले की जमीन खिसकी है, उसने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तो यह कि आखिर गलतियां कहां हुईं और दूसरा यह कि मोदी वेव के बीच कांग्रेस के सामने क्या चुनौतियां हैं। उत्तर भारत के तीन में से दो राज्यों, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजों ने साफ किया है कि वोटरों ने दो राष्ट्रीय पार्टियों को ही वोट दिया है। दोनों राज्यों में सपा, बसपा, जेडीयू और आम आदमी पार्टी (आप) का खाता भी नहीं खुला। मध्य प्रदेश में आप को 0.54 फीसदी, बसपा को 3.40, जेडीयू को 0.02 और सपा को 0.46 फीसदी वोट मिले। छत्तीसगढ़ में आप को 0.93 फीसदी, बसपा को 2.05 फीसदी और सपा को 0.04 फीसदी वोट मिले। राजस्थान में हालांकि इंडियन नैशनल लोकदल ने 1 और भारत आदिवासी पार्टी ने 3 सीटें जीतीं। बसपा को भी 2 सीटें मिलीं। लेकिन मुख्य मुकाबला यहां भी दो राष्ट्रीय दलों के बीच रहा। ध्यान रहे, मध्य प्रदेश में आप ने 70 से ज्यादा उम्मीदवार खड़े किए थे और सपा भी वहां 46 सीटों पर लड़ी थी। कहा जा रहा है कि करीबी लड़ाई वाली कई सीटों पर सपा ने हार-जीत के अंतर से ज्यादा वोट पाए। बसपा, सपा और आप जैसे दलों के चुनाव मैदान में उतरने से विरोधी वोट बिखर गए, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। ऐसे में अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सपा और राजस्थान में भारत आदिवासी पार्टी जैसे दलों का साथ मिला होता तो वह फायदे में रहती। यही वजह है कि चुनाव नतीजों के बाद सपा ने कहा कि कांग्रेस को उसका घमंड ले डूबा। जेडीयू भी कह रही है कि कांग्रेस को मान लेना चाहिए कि वह अकेले नहीं जीत सकती। पूरे चुनाव में कांग्रेस बीजेपी की तैयार की गई पिच पर खेलती दिखी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर खेलने की कोशिश की। कमलनाथ और भूपेश बघेल ने सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए बीजेपी के खेल में उसे ही मात देने की कोशिश की। लेकिन जनता ने उन्हें इस खेल का प्रॉक्सी खिलाड़ी समझ नकार दिया। कांग्रेस में लंबे समय तक रहे गुलाम नबी आजाद ने नतीजों के बाद एक बयान दिया है कि कांग्रेस अपने आप को अल्पसंख्यकों का चैंपियन कहती रही, लेकिन उसके अजेंडे में मॉइनॉरिटी के मुद्दे नदारद ही रहे। राजस्थान की सोशल सिक्यॉरिटी और ओल्ड पेंशन के साथ-साथ छत्तीसगढ़ की गृहलक्ष्मी और 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम भी नहीं चली। लेकिन बीजेपी की 'लाडली बहना' चल गई। कांग्रेस का जातीय जनगणना का दांव सही नहीं पड़ा। मध्य प्रदेश में परंपरागत सवर्ण वोट बैंक भी बीजेपी के पाले में चला गया। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव के मुकाबले देखें तो कांग्रेस के वोट शेयर में बेहद मामूली सी गिरावट है। इस बार कांग्रेस को 40.40 फीसदी वोट मिले हैं जबकि पिछली बार 40.89 फीसदी वोट मिले थे। यानी वोट प्रतिशत मात्र 0.49 फीसदी घटा है। मगर बीजेपी को वहां इस बार 48.55 फीसदी वोट मिले हैं जो कि पिछली बार से 7 फीसदी ज्यादा हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का वोट शेयर पिछली बार 43.90 फीसदी था तो इस बार उसे 42.23 फीसदी वोट मिले हैं। मगर बीजेपी को इस बार 46.27 फीसदी वोट मिले। जाहिर है, उसका वोट शेयर 13 फीसदी से ज्यादा बढ़ा। राजस्थान में बीजेपी ने 41.69 प्रतिशत वोट हासिल किए, जबकि कांग्रेस को 39.53 फीसदी वोट मिले। पिछली बार भले ही कांग्रेस जीती थी, लेकिन दोनों पार्टियों के वोट शेयर में अंतर सिर्फ 0.5 फीसदी का था। हालांकि इस बार बीजेपी के वोटिंग परसेंटेज में 2.92 फीसदी का सुधार हुआ है, जिसका फायदा उसे मिला। जाहिर है, उत्तर भारत में जबर्दस्त हार झेलने वाली कांग्रेस को तेलंगाना में मिली अप्रत्याशित जीत का बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस ने उत्तर भारत में चुनाव थके-हारे चेहरों को लेकर लड़ा। प्रचार की अगुआई करते भी वही लोग दिखे। इसके उलट सीएम के चेहरे को लेकर बीजेपी का सस्पेंस काम कर गया।

सनातन भारत को मजबूती देने वाले परिणाम

ललित गर्ग

भारत के राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव परिणाम ने न केवल मतदाता के जागरूक होने का संकेत दिया है बल्कि भारत को भारतीय मूल्यों के अनुरूप विकसित होते देखने की उसकी मंशा को भी उजागर कर दिया है, इसलिये इन चुनावों में तुष्टीकरण, साम्प्रदायिकता, जातीयता के बजाय विकास एवं विकसित भारत के नाम वोट पड़े। मतदाताओं ने जो जनादेश दिया है उससे एक बार फिर सिद्ध हो गया है कि भारत में लोकतंत्र कायम है और इसकी जीवंतता के लिये मतदाता जागरूक है। मतदाता को ठगना या लुभाना अब नुकसान का सौदा है। इन चुनावों में मोदी लहर बरकरार रही, भले ही आप श्रेय चाहे 'लाड़ली बहना' को दें, तीन तलाक को दें, तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था को दें, सनातन मूल्यों को दे। देश में पहली बार एक दल के नाम पर चुनाव हुए, नये भारत-सशक्त भारत के नाम पर चुनाव हुए, इन चुनावों में व्यक्ति गौण हो गए। ये चुनाव ज्यादा महत्वपूर्ण एवं उत्साह वाले इसलिये बने कि इन्हीं चुनावों को 2024 के लोकसभा चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा था। उस लिहाज से निस्संदेह तीनों राज्यों में बीजेपी को मिली प्रचंड एवं स्पष्ट ऐतिहासिक जीत बहुत बड़ी है और बहुत कुछ बयां कर रही है।

अगले लोकसभा चुनाव से चार माह पहले हुए इन विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा था। उसी नजरिये से देखें तो यह सेमीफाइनल मुकाबला लगभग एकतरफा नजर आता है। उत्तर भारत के तीनों राज्यों में भाजपा ने जबर्दस्त जीत हासिल की है, जबकि दक्षिण भारत के एक और राज्य में कांग्रेस सत्ता पाने में सफल रही है। लेकिन वहां भी भाजपा का एक सीट से 8 तक पहुंचना भाजपा के लिये शुभता का संकेत है। आज भी किसी दल के नेता में यह क्षमता नहीं है कि देश की बजाय पार्टी के ध्वज तले आगे बढ़ सके, वे ही दल एवं नेता प्रभावी हैं जो देश के अस्तित्व एवं अस्मिता को नये शिखर देने के संकल्पबद्ध हैं, न कि षड़यंत्रपूर्वक किन्हीं अल्पसंख्यकों को एक दल-विशेष को वोट देने को उकसा रहे हैं। जनता ने परिवारवादी सोच को नकार दिया, भ्रष्टाचार के खिलाफ जमीन पर सच देखने को मतदाता आतुर है, राष्ट्र को तोड़ने की साजिशों पर भी मतदाता सतर्क एवं सावधान हुआ है। अगले लोकसभा चुनावों में अधिक समय बाकी नहीं है। जनता की आंखें सरकारों के कामकाज पर टिकी हुई रहेंगी। कई प्रकार की अपेक्षाएं बाट जोह रही हैं। लघु जनादेश ही बड़े जनादेश का आधार बनता है। इसलिये इस बार का जनादेश विशेष है, जनता के मन में क्या है, उसकी अभिव्यक्ति है। पिछले सरकारों के दौर में सत्ता-संघर्ष के चलते जाति-धर्म और सम्प्रदायों के नाम पर देश पीछे जा रहा था, विकास अवरुद्ध था, निवेश ठहरा हुआ था, रोजगार खो गया था, देश के भीतर एवं सीमाओं पर आतंकवाद को पनपाया जा रहा था, हिंसा एवं आतंकवादी घटनाओं से देश की आत्मा लहूलुहान थी। कोई नए भारत का, औद्योगिक भारत का सपना नहीं देख रहा था। राष्ट्रवाद की चर्चा करना पाप जैसा लगता था। इन हालातों को बदलने के लिये मोदी-संकल्पों ने फिजां ही बदल दी। दलों से ऊपर उठकर देशहित, राष्ट्रीयता, विकास एवं आमजन सर्वोपरि हो गया है, इसकी सार्थक निष्पत्तियां एवं स्वर लहरियां इन चुनावों परिणामों में सुनी जा सकती है।

दरअसल, तीन राज्यों में हार से कांग्रेस की राजनीतिक चुनौतियां कई गुना बढ़ गई हैं। यह हार अपने आप में बड़ा सदमा है, कांग्रेस की सत्ताकांक्षा एवं उससे जुड़ी परिवारवादी सोच, बड़बोलापन, मुक्त रेवड़ियों का सहारा, मोदी विरोध के नाम पर घटिया शब्दावली का प्रयोग, ऐसे कारणों की समीक्षा कांग्रेस को करनी ही पड़ेगी। भाजपा की जीत का श्रेय मोदी को जाता है, पर कांग्रेस की हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? अब आसन्न चुनौती अगले लोकसभा चुनाव और विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के आंतरिक समीकरण होंगे। नया विपक्षी गठबंधन बनने के चंद महीने में हुए इन विधानसभा चुनावों में एकजुटता के बजाय अंतर्विरोधों का ही संदेश गया और बहुत कर्कश स्वर में गया। इन चुनाव परिणामों से न केवल कांग्रेस बल्कि समूचे विपक्ष के नेताओं को सीखना होगा, सबक लेना होगा। लोकलुभावन योजनाएं एवं मुफ्त-संस्कृति काम नहीं आयेगी। महत्वाकांक्षा एवं सबसे पुरानी पार्टी होने के अहंकार से बाहर आना होगा। बुनियादी स्तर पर संगठन और आम जनता के बीच जाकर विश्वास जीतना होगा, नीति एवं नियत को बदलना होगा। भारत की राजनीति एक नये बदलाव की ओर अग्रसर है, उस बदलाव के बिन्दुओं को स्वीकारना होगा।

तीन राज्यों की ऐतिहासिक जीत ने भाजपा का मनोबल निश्चित रूप से बढ़ेगा। भाजपा एवं मोदी की सोच, नीतियां, योजनाएं एवं दृष्टिकोण भी उनको अधिक साहसित एवं मनोबली बनायेंगे। उनके आदिवासी विकास का संकल्प, महिलाओं की भूमिका और 33 प्रतिशत आरक्षण का आश्वासन, समान नागरिक संहिता, सांस्कृतिक मूल्यों का विकास, युवाओं के लिये रोजगार, विश्वगुरु बनाने की कार्ययोजना, देश की सुरक्षा एवं साख जैसे गंभीर मुद्दों के निस्तारण के लिए भी मोदी ही दम रखते जान पड़ते हैं। देश को आगे बढ़ाना है तो तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार से मुक्त होना आवश्यक है। मोदी ही गारण्टी की गारण्टी हैं, लेकिन इसमें अहंकार नहीं है, मोदी ने अपनी जगह पार्टी एवं देश की जनता को ही प्रमुखता दी, देश की जनता को हमेशा आगे रखा है। उन्होंने चुनावी सभाओं में साफ कहा कि पार्टी का चेहरा कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि कमल का फूल है, साफ-सुथरी नीतियां हैं, देश को सशक्त बनाने का संकल्प है। निश्चित ही इस बार के चुनाव परिणाम सनातन भारत को मजबूती देने वाले हैं, सनातन का अर्थ सच्चा भारत, सच्ची मानवीयता एवं उदात्त जीवन मूल्य।

तीन राज्यों का जनादेश का केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही महत्त्व नहीं है, इसका सामाजिक क्षेत्र में भी महत्त्व है। जहाँ राजनीति में मतों की गणना को जनादेश कहते हैं, वहां अन्य क्षेत्रों में जनता की इच्छाओं और अपेक्षाओं को समझना पड़ता है। जनादेश और जनापेक्षाओं को ईमानदारी से समझना और आचरण करना सही कदम होता है और सफलता सही कदम के साथ चलती है। भारत के लोगों ने इस देश की बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था के औचित्य को न केवल स्थापित किया है बल्कि यह भी सिद्ध किया है कि मतदाता ही लोकतन्त्र का असली मालिक होता है। एक दिन का राजा ही हमेशा वाले राजा से बड़ा होता है। लोकतन्त्र की खासियत इसी बात में है कि मतदाता हर पांच वर्ष बाद अपनी विकास की बात करने वाले एवं स्वस्थ मूल्यों के धारकों को उनकी काबिलियत के मुताबिक चुनता है। तीनों राज्यों में मतदाताओं को लगा कि भाजपा का शासन एवं नीतियां उनके लिए ठीक है। इन चुनावों ने कांग्रेस एवं विपक्षी दलों की सत्ता लालसा पर लगाम लगा दी है। उनके लिये ये नतीजे खतरे की घंटी भी हैं और एक चुनौती भी हैं कि मतदाताओं को हल्के में नहीं लेना चाहिए, न अपनी जागीर समझना चाहिए। आज का मतदाता जागरूक है और परिपक्व भी है। अवसर आने पर किंग मेकर की भूमिका निभाने वाली जनता उसकी भावनाओं एवं अपेक्षाओं से खिलवाड़ करने वालों को जमीन भी दिखा देती है। कांग्रेस मुक्त भारत की ओर अग्रसर पार्टी को तेलंगाना की जीत संजीवनी देने वाली है, यह जीत कांग्रेस के लिए लिए एक बड़ी राहत भी देने वाली है। लेकिन उसे समझना होगा कि रेवड़ियां बांटने की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और बिना विचारधारा बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता।

निश्चित ही भाजपा ने इन राज्यों में नया इतिहास रच डाला और नया कीर्तिमान स्थापित किया। एक बार फिर यह साबित हुआ मोदी एक राष्ट्रीय नेता एवं जन-जन की धड़कन है। प्रांतों में नरेन्द्र मोदी का वर्चस्व कायम है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद इन नतीजों ने साबित किया कि मोदी आज भी देश के सबसे लोकप्रिय और बड़े नेता हैं और विकास के सारथी हैं। देश की जनता अब विकास पर वोट डालती है न कि मुफ्त की सुविधाओं के झांसे में आती है, उसे सुशासन एवं सुनीतियां ही स्वीकार्य हैं। भाजपा की जीत का अर्थ निश्चित ही सुशासन भी है और इससे तीनों राज्यों के लोगों के कल्याण व विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा। इसी की अपेक्षा के लिये जनता ने एकतरफा वोट डाले। मोदी ने राजनीति को एक नई दिशा दी है और वह है कि राजनीतिक चालें शुद्ध विकास एवं स्वस्थ लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़कर ही लम्बा जीवन पा सकती हैं।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

यागचूडामण्युपनिषद् (भाग-5)

गतांक से आगे...

कुण्डलिनी शक्ति कन्द के ऊर्ध्वभाग में आठ कुण्डलों की आकृति में व्याप्त होकर ब्रह्म द्वार के मुँह को अपने मुख से ढककर सदैव स्थित रहती है। जिस मनोमय ब्रह्म द्वार (सुषुम्ना) में प्रवेश किया जाता है, उसी द्वार (मुख) को अपने मुख से ढककर यह परमेश्वरी शक्ति (कुण्डलिनी) सोई रहती है। वह्नियोग (अग्नियोग) के द्वारा जाग्रत होकर यह प्रकाश के रूप में मन और प्राणवायु के साथ सुषुम्ना नाड़ी के भीतर होकर सुई की तरह ऊपर की ओर चलती है।

कुंजी के द्वारा जिस तरह से घर का किवाड़ (ताला) खोलते हैं, उसी प्रकार कुण्डलिनी के द्वारा योगी लोग मुक्ति का द्वार खोल लेते हैं। दृढ़तापूर्वक पद्मासन लगाकर हाथों को ऊपर-नीचे गोदी में रखकर सम्पुटित करे, पुनः सिर नीचा करके ठोड़ी को छाती से लगाये, इसके बाद ब्रह्म में ध्यान को एकाग्र करके, बार-बार श्वास को भीतर खींचे और बाहर निकाले। प्राणवायु अन्दर ले जाए और अपान वायु ऊपर ले जाए। इस तरह प्राणायाम करने से मनुष्य को अतुल शक्ति की अनुभूति होती है। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास के श्रम से जो पसीना निकलता है, उसे शरीर में ही मसल लेना चाहिए तथा नमकीन, खट्टे, कडुवे पदार्थों का परित्याग करना चाहिए और दूध एवं दूध से बने भोजन का विशेष रूप से प्रयोग करना चाहिए।

ब्रह्मचारी और मिताहार वाला योगी यदि योग के अभ्यास में लग जाए, तो एक वर्ष में ही योग की सिद्धि प्राप्त कर लेगा, इसमें सन्देह नहीं करना चाहिए। योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन ही लेना चाहिए, (आधा पेट भोजन, चौथाई पानी तथा) चौथाई भाग खाली रखे। इस प्रकार भगवान् को समर्पित करके जो भोजन करता है, उसे मिताहारी कहते हैं।

क्रमशः ...

डॉ. भीमराव अम्बेडकर

निधि अविनाश

अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती के रूप में मनाई जाती है। वह एक न्यायविद, अर्थशास्त्री और दलित नेता थे, जिन्होंने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया और स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। पश्चिमी भारत के एक दलित महान परिवार में जन्मे अंबेडकर को अपने उच्च जाति के स्कूली साथियों द्वारा कई बार अपमानित किया जाता था। उनके पिता भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। बड़ौदा (अब वडोदरा) के गायकवाड़ (शासक) द्वारा छात्रवृत्ति से सम्मानित, अम्बेडकर ने संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। उन्होंने गायकवाड़ के अनुरोध पर बड़ौदा लोक सेवा में प्रवेश किया, लेकिन, फिर से उनके उच्च जाति के सहयोगियों द्वारा उनपर दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने कानूनी अभ्यास और शिक्षण की ओर रुख किया और दलितों के बीच अपना नेतृत्व स्थापित किया। दलितों (या हरिजन, जैसा कि गांधी उन्हें कहते थे) के लिए बोलने के महात्मा गांधी के दावे का विरोध करते हुए, अम्बेडकर ने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स (1945) लिखा। 1947 में अंबेडकर भारत सरकार के कानून मंत्री बने। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में एक प्रमुख भूमिका निभाई, अछूतों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त किया।

29 अगस्त 1947 को डा.आम्बेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना कि लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 26 नवम्बर 1949 को संविधान सभा ने उनके नेतृत्व में बने संविधान को अपना लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद बोलते हुए डा.आम्बेडकर ने कहा मैं महसूस करता हूं कि भारत का संविधान साध्य है, लचीला है पर साथ ही यह इतना मजबूत भी है कि देश को शांति और युद्ध दोनों समय जोड़ कर रखने में सक्षम होगा। मैं कह सकता हूं कि अगर कभी कुछ गलत हुआ तो इसका कारण यह नही होगा कि हमारा संविधान खराब था बल्कि इसका उपयोग करने वाला मनुष्य ही गलत था। 1951 में उन्होंने सरकार में अपने प्रभाव की कमी से निराश होकर इस्तीफा दे दिया। अक्टूबर 1956 में, हिंदू सिद्धांत में अस्पृश्यता के कारण निराशा में, उन्होंने हिंदू धर्म को त्याग दिया और नागपुर में एक समारोह में लगभग 200,000 साथी दलितों के साथ बौद्ध बन गए। अम्बेडकर की पुस्तक द बुद्धा एंड हिज़ धम्म 1957 में मरणोपरांत प्रकाशित हुई, और इसे 2011 में द बुद्ध एंड हिज़ धम्म ए क्रिटिकल एडिशन के रूप में एक बार फिर प्रकाशित किया गया, जिसे आकाश सिंह राठौर और अजय वर्मा द्वारा संपादित, प्रस्तुत और एनोटेट किया गया। संविधान के रचियता डॉ. भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी।

नेहरू-राजीव के रिकॉर्ड तोड़ने की दिशा में बढ़ रहे हैं मोदी

नीरज कुमार दुबे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत से खुश होकर ऐलान किया कि इस हैट्रिक ने 2024 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है तो उत्साहित भाजपा सांसदों ने संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में प्रधानमंत्री मोदी के सामने %तीसरी बार मोदी सरकार% और %बार बार मोदी सरकार% का नारा लगा कर देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा दिया। देखा जाये तो 2024 का लोकसभा चुनाव होने में तीन-चार महीने का समय बचा है। इसलिए अगला चुनाव जीतने के लिए जहां भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है वहीं विपक्ष भी एकजुट होकर पूरा जोर लगा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने कामकाज और देश के लिए हासिल की गयी उपलब्धियों पर जनता का समर्थन एक बार फिर मिलने की उम्मीद है। हम आपको बता दें कि मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में राम मंदिर बनाने, अनुच्छेद 370 हटाने, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से आजादी दिलाने, देश की महिलाओं को संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण दिलाने, सीएए लाने, देश की सीमाई सुरक्षा को मजबूत बनाने तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने समेत कई अन्य वादे किये थे जिन्हें पूरा कर उन्होंने %मोदी की गारंटी% शब्द को सार्थक सिद्ध कर दिया है।

देखा जाये तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशाल राजनीतिक कद जैसा कोई अन्य नेता किसी भी पार्टी के पास नहीं है। मोदी जिस तरह से अपने बलबूते अपनी पार्टी को किसी भी राज्य का या केंद्र का चुनाव जिता सकते हैं उतनी राजनीतिक क्षमता किसी अन्य नेता में नजर नहीं आती। मोदी की बातों और वादों पर जितना विश्वास देश की जनता करती है वैसी साख किसी अन्य नेता की बातों और वादों की नहीं है। मोदी अगर जनता से वादे पूरे होने की गारंटी हैं तो मोदी भाजपा के लिए भी जीत की गारंटी हैं। देश की राजनीतिक परिस्थितियां दर्शा रही हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव भाजपा के लिए संभवतः 2019 से भी ज्यादा अच्छे परिणाम ला सकता है। लेकिन भाजपा सिर्फ अच्छे चुनावी परिणाम के लिए काम नहीं कर रही है। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा को दूसरों की ओर से कायम पुराने रिकॉर्ड तोड़ने और नये रिकॉर्ड बनाने का ऐसा जुनून सवार है कि वह 2024 में एक बड़े रिकॉर्ड की बराबरी करने और एक बड़े रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए काम कर रही है।

हम आपको बता दें कि भाजपा यदि 2024 के लोकसभा चुनावों को भी जीत जाती है तो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के लगातार तीन बार देश का प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। इसके साथ ही भाजपा 2024 में 1984 के संसदीय चुनावों में राजीव गांधी को मिली 404 सीटों का रिकॉर्ड तोड़ने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। इसीलिए भाजपा नेताओं ने नारा दे भी दिया है कि %अबकी बार 400 पार%। देखा जाये तो नारा देना आसान है लेकिन उसे हकीकत में बदलना बेहद कठिन है, लेकिन आज के राजनीतिक दौर की एक सच्चाई यह भी है कि मोदी है तो मुमकिन है।

सवाल यह है कि 2024 में मोदी कैसे बनाएंगे नया रिकॉर्ड? कहां से आयेंगी 400 से ज्यादा सीटें? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने और आंकड़ों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा बहुत पहले ही जमीन पर काम करना शुरू कर चुकी है। इस समय देखा जाये तो 13 राज्यों में भाजपा की अपने बलबूते सरकार है। इन राज्यों की संसदीय सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 80, उत्तराखण्ड में पांच, असम में 14, छत्तीसगढ़ में 11, गोवा में 2, गुजरात में 26, हरियाणा में 10, मध्य प्रदेश में 29, महाराष्ट्र में 48, मणिपुर में 2, राजस्थान में 25, अरुणाचल प्रदेश में 2 और त्रिपुरा में 2 सीटें हैं। इसके अलावा भाजपा जिन राज्यों में गठबंधन सरकार में शामिल है उनमें मेघालय में 2, सिक्किम, नगालैंड और पुडुचेरी में 1-1 लोकसभा सीट शामिल हैं। यदि इन सीटों का कुल योग कर लें तो 261 सीटें बनती हैं। इसके अलावा यदि अन्य पार्टियों के शासन वाले राज्यों में भाजपा की लोकसभा सीटों की बात करें तो पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों में दिल्ली, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी शानदार प्रदर्शन किया था और अभी के हालात को देखें तो भाजपा इन राज्यों में अपने पिछले प्रदर्शन से ज्यादा अच्छे परिणाम 2024 में देने की स्थिति में नजर आ रही है। साथ ही यदि केंद्र शासित प्रदेशों की संसदीय सीटों की बात करें तो जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, दादरा और नागर हवेली में भी 2024 में भाजपा की जीत के आसार नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा जिस तरह दक्षिण के अन्य राज्यों में भी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है उसके परिणाम खासतौर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में देखने को मिल सकते हैं क्योंकि हाल में कई चुनावों में भाजपा ने इन राज्यों में अपना वोट प्रतिशत भी बढ़ाया है और अपनी पार्टी के संगठन को भी दुरुस्त किया है।

देखा जाये तो एक बात साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इतनी लंबी लकीर खींचने में विश्वास रखते हैं जहां तक कोई सोच भी नहीं सकता हो। इसलिए जब भाजपा ने %अबकी बार 400 पार% का नारा दिया है तो उस पर विपक्ष को कोई हैरानी नहीं हो रही है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव ने तो कह भी दिया है कि भाजपा की नीति है कि वह नया रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं इसलिए यह राजीव गांधी के जमाने में कांग्रेस की ओर से बनाये गये रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं। यही नहीं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी विश्वास जता दिया है कि जितनी सीटें पिछले लोकसभा के चुनाव में आई थीं, इस बार उससे अधिक सीटों पर भाजपा विजय प्राप्त करेगी। पार्टी के अन्य नेता भी इसी तरह का विश्वास व्यक्त कर रहे हैं।

बहरहाल, साल 2023 की शुरुआत त्रिपुरा, मेघालय और नगालैंड में चुनावी जीत के साथ और साल का अंत भी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी जीत के साथ करने वाली भाजपा के लिए 2024 कैसा रहेगा यह तो आने वाला वर्ष ही बतायेगा लेकिन इतना तो दिख ही रहा है कि हालिया विधानसभा चुनाव परिणामों से भाजपा का जोश एकदम हाई है।

आज का इतिहास

1935 माइकल जोसेफ सैवेज न्यूजीलैंड के 23 वें प्रधान मंत्री बने।
1953 व्लादिमीर नाबोकोव ने अपना विवादास्पद उपन्यास लोलिता पूरा किया, इसे शुरू करने के पांच साल बाद।
1956 मेलबर्न ओलंपिक में, 14 वर्षीय तैराक सैंड्रा मोर्गनबेक ने ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का खिताब जीता।
1958 इटली में विश्व की सबसे लम्बी और अत्यंत महत्वपूर्ण सुरंग बनाने का काम आरंभ हुआ। इसकी खुदाई का काम 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद 14 अगस्त सन 1964 को पूरा हुआ।
1975 प्रांतीय आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के चार सदस्यों ने मैरीलेबोन, लंदन के बालकोम्ब स्ट्रीट पर एक घर में दो लोगों को बंधक बना लिया और छह दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया।
1978 स्पेन के लोगों ने लोकतंत्र के पक्ष में वोट डाला और जनमत संग्रह में 40 साल के निरंकुश शासन को समाप्त करने के लिए एक नए संविधान को मंजूरी देने का अनुमान लगाया।
1983 येरुशलम में बस में हुये धमाके से इजरायल के छह नागरिकों की मौत हुई।
1988 ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र को स्व-शासन प्रदान किया गया था।
1989 यह दावा करते हुए कि वह %फेमिनिज्म% से जूझ रही थीं, 25 वर्षीय मार्कलेपाइन ने मॉन्ट्रियल के इकोले पॉलिटेक्निक में आत्महत्या करने से पहले चौदह महिलाओं की हत्या कर दी।
1994 किए गए अध्ययनों के अनुसार, बर्कशायर में विंडसर कैसल के नीचे लगभग 1 पाउंड तेल पड़ा हो सकता है। रानी विंडसर कैसल के मैदान में तेल ड्रिलिंग की अनुमति देने के लिए सहमत हो गई है।
1998 ह्यूगो शावेज वेनेजुएला के राष्ट्रपति चुने गये।
2005 पीपुल्स आर्म्ड पुलिस के सदस्यों ने डोंग्झू, चीन के गुआंगडोंग में कई लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी, जो एक नए बिजली संयंत्र का निर्माण करने के लिए सरकारी योजनाओं का विरोध कर रहे थे।
2006 नासा द्वारा सामने आई तस्वीरों से साबित होता है कि हाल ही में पिछले 7 सालों में मंगल ग्रह पर 2 गुल्लियों से पानी बह रहा है।

मध्य प्रदेश में प्रचंड जीत का असली नायक कौन?

सिद्धार्थ शंकर गौतम

2003 में साध्वी उमा भारती के चेहरे, स्व. अनिल माधव दवे के संगठन शास्त्र तथा पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के विरुद्ध जबरदस्त एंटी-इन्कंबेंसी से भाजपा ने मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए 42.50 प्रतिशत वोटों के साथ 173 विधानसभा सीटें प्राप्त की थीं किंतु 2023 में सत्ता में रहते हुए बिना मुख्यमंत्री चेहरे के यदि भाजपा 48.57 प्रतिशत वोटों के साथ 163 सीटों पर विजयी हुई है तो यह उसके इतिहास की सबसे बड़ी जीत है।

2018 में भाजपा को प्राप्त 41.02 प्रतिशत वोटों में इस बार 7.55 प्रतिशत का इजाफा होना यह दर्शाता है कि पार्टी ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पैरों तले उसकी राजनीतिक जमीन खिसका दी है। हालांकि भाजपा की इस प्रचंड जीत के बावजूद शिवराज कैबिनेट के 31 में से 12 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा है और यह उन मंत्रियों के विरुद्ध उनके क्षेत्र की जनता की नाराजगी को दर्शाता है। भाजपा ने बसपा का 2.5 प्रतिशत, निर्दलीयों का 3 प्रतिशत तथा सपा, आप व अन्य का 3 प्रतिशत वोट अपने पाले में किया। इस जीत का श्रेय कई फैक्टर्स को दिया जा सकता है किंतु वास्तविकता में इस जीत का असली नायक कौन है?

लोकतंत्र में एम-वाई अर्थात मुस्लिम-यादव समीकरण के बारे में सुनकर बड़े हुए लोगों को मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन ने नई परिभाषा से परिचित करवाया है जहां एम अर्थात महिला और वाई अर्थात यूथ। राजनीति का यह न्यू नार्मल अब आगामी विधानसभा चुनावों से लेकर 2024 के आम चुनाव में भाजपा की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा है। प्रदेश में शिवराज सिंह ने इसी न्यू नार्मल के चलते %मामा% की छवि बनाई जो पिछले 18 वर्षों से उन्हें राजनीतिक बल देती जा रही है। चुनाव परिणाम देखकर यदि यह कहा जाए कि प्रदेश में शिवराज ही लाड़ले और भाजपा ही लाड़ली है, तो अतिश्योक्ति नहीं होगी।

मतदाताओं के मौन, संगठन की सरकार को लेकर प्रतिकूल रिपोर्ट तथा कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाते मीडिया ने कांटे की टक्कर है का नारा बुलंद किया तो ऐसा प्रतीत हुआ कि क्या वास्तव में सरकार के विरुद्ध एंटी-इन्कंबेंसी की बयार चल रही है? जब शिवराज सिंह से भी यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट कहा, कोई कांटें की टक्कर नहीं है, लाड़ली बहनों ने सारे कांटें निकाल दिए हैं।

अब जबकि अंतिम चुनाव परिणामों का विश्लेषण हो रहा है तो उनकी यह बात सत्य साबित होती दिख रही है। एक करोड़ 31 लाख महिलाएं, जो लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित हैं और वर्तमान में 1250 रुपए प्रतिमाह का लाभ ले रही हैं, उन्होंने भाजपा की झोली वोटों से भर दी है। 34 से अधिक विधानसभा सीटों पर लाड़ली बहनों ने 7 से 8 प्रतिशत अधिक मतदान किया। इसके अलावा महिलाओं ने शिवराज सिंह के इमोशनल कार्ड के चलते भी उनका साथ दिया। लड्डू या जाऊं ने केंद्रीय नेतृत्व को भी कहीं न कहीं असहज किया और चुनावी रण के अंतिम प्रहर में शिवराज सिंह फ्री हिट पर खेलते नजर आए।

165 से अधिक जनसभाओं, रैलियों, रोड शो ने शिवराज की राह के भी कांटें निकाल दिए। पूर्व में लाड़ली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आदि का सफल क्रियान्वयन महिलाओं के बीच शिवराज सिंह को भरोसेमंद साबित कर गया अन्यथा तो कमलनाथ ने भी महिलाओं के लिए नारी वंदन योजना की घोषणा की थी किंतु मामा की छवि ने उनकी योजना को ध्वस्त कर दिया। लाड़ली बहना का जादू इस तथ्य से भी साबित होता है कि भाजपा ने 27 महिलाओं को चुनावी रण में उतारा था जिसमें से 21 को विजयश्री प्राप्त हुई है जबकि कांग्रेस की 29 महिला प्रत्याशियों में से मात्र 7 ही चुनाव जीत सकी हैं।

वोटों के लिहाज से मध्य प्रदेश में देश की सर्वाधिक वनवासी आबादी है। 2018 में मालवा-निमाड़ के वनवासी क्षेत्र ने कांग्रेस का हाथ थामा तो भाजपा सत्ता से दूर हो गई थी। हालांकि 2020 में मुख्यमंत्री बनने के पश्चात शिवराज सिंह ने अपना सर्वस्व इस क्षेत्र में झोंक दिया। युवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. निशांत खरे ने मुख्यमंत्री का प्रतिनिधि बनकर वनवासी क्षेत्रों को मथने का काम किया। पेसा कानून ने वनवासी वर्ग को भाजपा के नजदीक कर दिया। मालवा-निमाड़ की 66 में से 48 सीटें जीतकर भाजपा ने कांग्रेस के मजबूत वोट बैंक को उससे दूर कर दिया जबकि 2018 में भाजपा को मात्र 29 सीटें ही इस क्षेत्र से मिली थीं। प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर में 9 की 9 विधानसभा सीटों पर कमल खिला। यहां राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को चुनावी मैदान में उतार कर संगठन ने उनकी क्षमताओं का भरपूर लाभ लिया और पूरे क्षेत्र में उनकी सक्रियता ने जयस, बाप जैसे दलों की रणनीति को फेल कर दिया। यहां तक कि दलित वर्ग की बहुलता वाली 35 में से 26 सीटों पर भाजपा विजयी रही।

केंद्रीय नेतृत्व ने जब तीन केंद्रीय मंत्रियों सहित 4 सांसद और राष्ट्रीय महासचिव सहित अन्य मोर्चा पदाधिकारियों को टिकट दिया तो ऐसा लगा कि अब प्रदेश में गुटबाजी चरम पर होगी किंतु केंद्रीय नेतृत्व ने व्यक्ति के चेहरे के स्थान पर कमल को ही चेहरा बना दिया। इससे सभी को फ्रीहैण्ड मिला और सभी ने अपने-अपने क्षेत्रों में अपेक्षा से बढ़कर परिणाम दिए।

हालांकि सांसद गणेश सिंह सतना से और केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते निवास से चुनाव हार गए किंतु इनके क्षेत्र में रहने से अन्य सीटों पर कार्यकर्ताओं में जोश भरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी, गृह मंत्री अमित शाह का कुशल प्रबंधन, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव की मोनिटरिंग, संगठन का बूथ मैनेजमेंट, सनातन का मुद्दा जैसे फैक्टर्स ने भी हृदय प्रदेश में कमल खिला दिया। तीन माह पूर्व हारी हुई 39 सीटों पर टिकट वितरण का फैसला भी पार्टी में पक्ष में रहा क्योंकि इनमें से 24 सीटों पर पार्टी उम्मीदवार को जीत मिली।

हालांकि इन सबके बीच अब मुख्यमंत्री कौन हो की चर्चा अहम है। फिलहाल तो मध्य प्रदेश में बंपर जीत दिलानेवाले पाँव-पाँव वाले भैया इस रेस में सरपट दौड़ लगाते दिख रहे हैं। वैसे भी अगर मध्य प्रदेश में बंपर जीत का नायक किसी को कहा जा सकता है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही हैं जिन्होंने अपनी दूरदर्शिता से पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के विरोध के बावजूद लाड़ली बहना जैसी योजना को जमीन पर उतारा और वोटों की बंपर फसल काट ली।

मोदी की गारंटी पर मतदाताओं ने जताया भरोसा

विनोद पाठक

राजस्थान में अब रुझान सीटों में तब्दील होने लगे हैं और भाजपा ने दूदू सीट से जीत की शुरुआत कर अपना खाता खोल लिया है। यह चुनाव पूरी तरह अशोक गहलोत की गारंटी बनाम नरेंद्र मोदी की गारंटी पर लड़ा गया था। रुझानों से साफ है कि भाजपा सत्ता में लौट रही है और एक बड़ी जीत दर्ज कर रही है। एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस को थोड़ी ऑक्सीजन मिलती दिख रही थी, लेकिन कांग्रेस के सारे पासे उल्टे पड़े हैं। बड़ा सवाल फिर वही कि भाजपा में कमान किसको मिलेगी? सुबह जब मतपत्रों से गिनती शुरू हुई तो भाजपा और कांग्रेस लगभग बराबरी पर थे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओल्ड पेंशन स्कीम की गारंटी का थोड़ा असर देखने को मिला, लेकिन जैसे ही ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू हुई तो थोड़ी ही देर में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णायक बढ़त बनाना शुरू कर दी। दोपहर आते-आते यह बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर जा चुकी थी। राजस्थान में 1993 से एक रिवाज चला रहा है, जब हर 5 साल में सरकार बदल जाती है। इस बार अपनी सरकार की योजनाओं के भरोसे अशोक गहलोत ने दम लगाया था कि वह इस रिवाज को बदल देंगे। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, महिलाओं को मोबाइल फोन, साल में 10,000 रुपए, वृद्धों को पेंशन, कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप/टैबलेट जैसी कई लोक-लुभावन गारंटी दी थीं। नतीजे से साफ है कि गहलोत की गारंटियों को मतदाता ने सिरे से नकार दिया है। यहां तक की उनके कई मंत्री भी चुनाव हार रहे हैं। दूसरी ओर, बिना चेहरे के भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव में उतरी थी। पार्टी ने युवाओं के पेपर लीक, किसानों के कर्जमाफी, महिलाओं के कानून व्यवस्था जैसे कई मुद्दे उठाए थे। भाजपा ने सनातन और तुष्टिकरण के मुद्दों पर भी चुनाव में बहुत अधिक फोकस किया था। एक तरह से पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर ले लिया था। कई बड़े नेता होने के बावजूद राजस्थान में चुनाव प्रधानमंत्री के इर्दगिर्द घूमा और इसका लाभ नतीजे में देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले राजस्थान में कांग्रेस की हार के कई मायने हैं। राजस्थान ने गांधी परिवार को भी झटका दिया है और अशोक गहलोत, जो खुद को नरेंद्र मोदी के समकक्ष नेता बताने पर तूले थे, उनकी राजनीति को गहरा धक्का लगा है। सचिन पायलट, जो इस पूरे चुनाव में खामोश रहे और बेहद कम सभाएं कीं और नतीजे से पहले कहीं नजर भी नहीं आ रहे तो यही माना जा रहा है कि अब अशोक गहलोत अध्याय समाप्त होकर सचिन पायलट अध्याय राजस्थान में फिर से शुरू होगा। जानकारों का तो यह तक कहना है कि गांधी परिवार भी शायद ही चाहता था। दूसरी ओर, भाजपा में नेतृत्व को लेकर आगामी एक सप्ताह काफी मंथन वाला रहने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, बाबा बालक नाथ, दीया कुमारी समेत के नाम उनके समर्थक मुख्यमंत्री की रेस में बताते हैं, लेकिन भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि राजस्थान की कुर्सी पर कौन बैठेगा? कुल मिलाकर भाजपा ने राजस्थान में कांग्रेस को गहरा धक्का दिया है। यह मोदी की गारंटी और चेहरे की जीत है।

आश्चर्यजनक नहीं हैं विधानसभा चुनावों के परिणाम

अवधेश कुमार

राज्य विधानसभाओं के चुनाव परिणाम उनके लिए किंचित भी आश्चर्य का विषय नहीं है जो इन राज्यों के बदले हुए राजनीतिक वातावरण को देख रहे थे। ये चुनाव परिणाम मतदाताओं के तात्कालिक संवेग की अभिव्यक्ति नहीं हैं। ये परिणाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और राज्य स्तर पर भाजपा के संदर्भ में बने संपूर्ण माहौल की परिणति हैं। देश का माहौल बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा भाजपा विरोधी प्रस्तुत कर रहे थे। अगर आप उनके पूर्व आकलनों को आधार बनाएं तो भाजपा को एक राज्य में भी विजय नहीं मिलनी चाहिए थी। मध्यप्रदेश में अगर बीच के 15 महीने की कमलनाथ सरकार को छोड़ दें तो करीब 19 वर्ष तक शासन करने के बावजूद भाजपा इतनी बड़ी विजय प्राप्त करती है तो फिर सामान्य विश्लेषणों से परिणाम की सच्चाई नहीं समझी जा सकती। मध्यप्रदेश में भाजपा को करीब 49% और कांग्रेस को 40% मत मिला है। 9% बहुत बड़ा अंतर है। राजस्थान में भी लगभग दो प्रतिशत मतों का अंतर है जबकि पिछली बार कांग्रेस को भाजपा से केवल करीब 0.25 प्रतिशत ज्यादा वोट मिले थे। छत्तीसगढ़ में भाजपा ने पिछली बार करीब 33 प्रतिशत और कांग्रेस ने 43 प्रतिशत वोट पाया था जबकि इस बार भाजपा को 45% से अधिक तथा कांग्रेस का वोट लगभग 39% तक सिमटा है यानी भाजपा ने 12% से ज्यादा मत हासिल किया, जबकि कांग्रेस का 4% वोट कट गया तो इस तरह के परिणामों के कारण क्या हैं? राजनीति में नेतृत्व मात्र चेहरा नहीं होता। वह विचारों और व्यवहार का समुच्चय होता है जिसके आधार पर मतदाता अपना मत तय करते हैं। नरेंद्र मोदी स्पष्ट विचारधारा को प्रतिबिंबित करते हैं जिसे केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारें नीतियों और व्यवहारों में लागू कर रही हैं। इसके साथ वक्तव्यों और व्यवहारों से भावी कदमों की झलक भी दी है। दरअसल, 2014 के बाद राजनीति, सत्ता और नेतृत्व को लेकर भारत के बदले हुए सामूहिक मनोविज्ञान और मतदाताओं के व्यवहार को न समझने के कारण ही ऐसे परिणाम आश्चर्य में डालते हैं। तेलंगाना में भी भाजपा अगर 2019 की विचारधारा और मुद्दों पर प्रखरता तथा सरकार के विरुद्ध आक्रामकता कायम रखती, ठाकुर राजा सिंह के निष्कासन की घोषणा नहीं करती और उसे दूसरे तरीके से संभालती तो परिणाम अलग आते। लोग बीआरएस की सत्ता बदलना चाहते थे, पर भाजपा हराने वाली सक्षम विकल्प नहीं थी। मतदाता कांग्रेस के साथ गए बावजूद भाजपा को लगभग 14% मत मिले हैं।

विपक्ष को मुद्दे नहीं, रणनीति बदलने की जरूरत

अमित शर्मा

कर्नाटक जीत के बाद उत्साह से लबरेज कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में करारी हार का सामना करना पड़ा है। इससे कांग्रेस के मनोबल पर असर पड़ा है। विपक्ष के वे सारे मुद्दे जिनके सहारे उसने इन चुनावों में भाजपा को घेरने की कोशिश की, बुरी तरह फ्लॉप साबित हुए। इसमें जातिगत जनगणना, जातिगत आरक्षण को बढ़ाना और पुरानी पेंशन योजना शामिल थी। चूंकि, कांग्रेस और विपक्ष इन्हीं मुद्दों के सहारे लोकसभा चुनावों में भी मोदी को घेरने की रणनीति बना रहा था, उसकी लोकसभा की उम्मीद भी कमजोर हुई है।

लेकिन यह इस मामले का एक पक्ष है। इस मामले का दूसरा पक्ष यह भी है कि इन्हीं मुद्दों के सहारे कांग्रेस ने राजस्थान, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना वोट शेयर लगभग बरकरार रखा है। राजस्थान में उसे 39.53 फीसदी वोट मिला। पिछले चुनाव के मुकाबले यह 0.23 फीसदी ज्यादा है। मध्यप्रदेश में कांग्रेस को 40.45 फीसदी मत मिले, जो पिछले चुनाव के मुकाबले 0.44 फीसदी कम है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 42.23 फीसदी मत मिले, जो उसके पिछले प्रदर्शन से 0.9 फीसदी कम है।

राजस्थान-छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपना वोट शेयर बरकरार रखने की सफलता ऐसे समय में पाई है, जब इन राज्यों में सरकार बदलने और एंटी इनकंबेंसी फैक्टर का भी सामना पड़ा। इन राज्यों में इनके नेताओं को आपस की कलह से जूझते हुए भी यदि अपना वोट शेयर बरकरार रखने में सफलता मिली है, तो इसका बड़ा श्रेय इन योजनाओं को दिया जा सकता है। तेलंगाना में कांग्रेस को 39.40 फीसदी मत मिला है, जो उसके पिछले प्रदर्शन से 11 फीसदी ज्यादा है। इसके मूल में भी इन मुद्दों का असर माना जा सकता है।

यह अवश्य कहा जा सकता है कि इन मुद्दों ने कांग्रेस के खाते में नए मतदाता वर्ग को जोड़ने में सफलता नहीं पाई, लेकिन तमाम कारणों के बीच यदि कांग्रेस अपना मत प्रतिशत बरकरार रखने में भी सफल रही है, तो इसका कारण इन मुद्दों और उसके मतदाताओं की कांग्रेस के प्रति समर्पण को कारण माना जा सकता है।

ध्यान देने की बात है कि इन चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत अचानक पांच से छह प्रतिशत तक बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में भाजपा के मत प्रतिशत में 13.33 फीसदी, मध्यप्रदेश में 7.6 फीसदी और राजस्थान में 3.61 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। समझने की बात यह भी है कि जब इन राज्यों के सबसे बड़े दल कांग्रेस के मत प्रतिशत में ज्यादा कमी नहीं आई, तो भाजपा के मत प्रतिशत में यह उछाल कहां से आया।

भाजपा के मत प्रतिशत में यह उछाल समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरएलपी और अन्य छोटे-छोटे दलों के मत प्रतिशत में भारी कमी के कारण आया। इस हाई प्रोफाइल चुनाव में भाजपा मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब रही कि लोगों को इधर-उधर वोट करके अपना वोट खराब नहीं करना चाहिए। मतदाताओं ने सरकार बनाने में अग्रणी दल को अपना वोट देकर अपने मत को सार्थक करने का विकल्प अपनाया। भाजपा के लिए यह सोच वरदान बन गई। गुजरात चुनावों में भी मतदाताओं के बीच इसी तरह की सोच देखी गई थी।

जनता दल यूनाइटेड नेता केसी त्यागी ने मीडिया से कहा कि जो मुद्दे जनता के आर्थिक-सामाजिक बदलाव से जुड़े होते हैं, वे मामले को हल किए बिना समाप्त नहीं होते। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि यूपी-बिहार सहित दक्षिण के तमाम राज्यों में वही राजनीतिक दल प्रमुख बने हुए हैं, जिन्होंने पिछड़े-दलित तबकों के सामाजिक कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया। यदि ये मुद्दे असरहीन होते, तो बिहार में जदयू-आरजेडी और दक्षिण में स्टालिन की पार्टी सरकार में न होती।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि उसने इंडिया गठबंधन को कम करके आंका। उसने सीट साझेदारी करना तो दूर, उन्हें प्रचार के लिए आमंत्रित तक नहीं किया। उलटे इनके नेताओं ने दूसरे दलों के नेताओं को अपमानित करने का काम किया। कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि अब उसके अकेले के शासन करने का दौर समाप्त हो चुका है।

भाजपा और नरेंद्र मोदी इसलिए सफल हैं क्योंकि वे सबको साथ लेकर चलने की रणनीति अपना रहे हैं। कोई राजनीतिक दल किसी छोटे जातीय समूह का भी प्रतिनिधित्व करता है, अमित शाह उसे अपने साथ लेने के लिए तैयार रहते हैं, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की है। यदि कांग्रेस और विपक्ष को आज की मोदी और भाजपा से मुकाबला करना है, तो उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ लेकर चलने की रणनीति अपनानी चाहिए।

राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन पर मंडराया खतरा

जितेंद्र भारद्वाज

मध्यप्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकार द्वारा बहाल की गई पुरानी पेंशन व्यवस्था पर अब खतरा मंडराने लगा है। इन दोनों राज्यों में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज कराई है। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन को लेकर पहले ही अपनी मंशा जाहिर कर दी है। देश में किसी भी सूरत में ओपीएस लागू नहीं किया जाएगा। खुद प्रधानमंत्री मोदी, इस विषय में अपनी राय स्पष्ट कर चुके हैं। एनपीएस में सुधार के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एनपीएस में बदलाव किया जा सकता है। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) के अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा है, ये संभावना नहीं, बल्कि तय समझें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अब पुरानी पेंशन व्यवस्था खत्म हो सकती है। इस बाबत एनएमओपीएस की कार्यकारिणी की बैठक में विचार होगा। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल होने तक कर्मचारियों का आंदोलन जारी रहेगा।

विजय कुमार बंधु ने बताया, राजस्थान सहित दूसरे प्रदेशों के चुनाव में ओपीएस का मुद्दा प्रभावी रहा है। अगर राजस्थान के पोस्टल बैलेट को देखें, तो उसमें 170 से अधिक सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे रही थी। इसी तरह मध्यप्रदेश के चुनावी नतीजों का विश्लेषण किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि ओपीएस ही चुनावी हार-जीत का प्रमुख कारण रहा है। यह कह सकते हैं कि हार-जीत के समीकरणों को तय करने के लिए जो अहम वजह होती हैं, उनमें से एक ओपीएस है। अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन व्यवस्था को खत्म किया जाता है, तो उसके खिलाफ सरकारी कर्मचारी आवाज उठाएंगे। इस आंदोलन को देश के हर हिस्से में ले जाया जा रहा है। इस कड़ी में पटना में 10 दिसंबर को पुरानी पेंशन लागू कराने के लिए सरकारी कर्मियों की एक बड़ी रैली आयोजित होगी।

केंद्र सरकार की तरफ से कई बार ओपीएस को लेकर बयान सामने आए हैं। उनमें कहा जा रहा है कि जो राज्य पुरानी पेंशन लागू कर रहे हैं, वहां पर भविष्य में वित्तीय संकट उत्पन्न हो सकता है। राज्यों को विभिन्न मदों के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता को बंद किया जा सकता है। पीएम मोदी, इस तरह की स्कीम को शॉर्ट कट पॉलिटिक्स का नाम दे चुके हैं। राजनीतिक दलों को ऐसी घोषणाओं से बचना चाहिए। ऐसी राजनीति, देश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक चुनाव में ओपीएस का वादा किया था। इसी तरह कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस बहाल कर दी गई थी। कांग्रेस ने मध्यप्रदेश के चुनाव की गारंटियों में ओपीएस को शामिल किया था। राजस्थान के चुनावी घोषणापत्र में कांग्रेस ने कहा था कि पुरानी पेंशन व्यवस्था को कानूनी दर्जा दिया जाएगा। राहुल और प्रियंका ने अपनी चुनावी रैलियों में दूसरे मुद्दों के साथ ओपीएस पर भरपूर फोकस किया था। जब यह स्कीम राजस्थान में लागू की गई, तब राज्य वित्त आयोग का कहना था कि इसके लिए 41 हजार करोड़ रुपयों की जरुरत होगी।

राजस्थान कैडर के पूर्व आईएएस राजीव महर्षि, जो केंद्रीय वित्त सचिव और राजस्थान के मुख्य सचिव जैसे

पदों पर काम कर चुके हैं, उन्होंने गत वर्ष ओपीएस को वित्तीय आपदा का नाम दिया था। उनका कहना था कि केंद्र और राज्य, दोनों के लिए यह स्कीम वित्तीय आपदा साबित होगी। राज्यों पर पहले से ही इतना कर्ज है कि उस स्थिति में ओपीएस, अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बर्बाद कर सकती है। सीएजी गिरिश चंद्र मुर्मु ने पुरानी पेंशन स्कीम के चलते राज्यों की वित्तीय स्थिति पर पड़ने वाले प्रभावों के जोखिमों को लेकर संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था, कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल किए जाने से फिस्कल रिस्क बना रहेगा। आरबीआई और 15वें वित्त आयोग ने भी इस बाबत संज्ञान लिया है। योजना आयोग (अब नीति आयोग) के पूर्व उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया ने ओपीएस को लेकर कहा था, ये सबसे बड़ी रेवड़ी है। एक तरफ तो राजस्व के घाटे को कम करने की बात की जाती है, लेकिन खर्चों को कैसे कम किया जाए, इसे पर कोई चर्चा नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में जिस रेवड़ी की बात कही है, वो सही है। पुरानी पेंशन सिस्टम, इसी तरह की सबसे बड़ी रेवड़ियों में से एक है।

पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार, कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है, तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में दो बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग (सिविल) में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96 फीसदी कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग (सिविल) के चार लाख कर्मियों में से 97 प्रतिशत कर्मी, हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी।

शिव गोपाल मिश्रा ने बताया, एनपीएस में कर्मियों जो पेंशन मिल रही है, उतनी तो बुढ़ावा पेंशन ही है। कर्मियों ने कहा है कि देश में सरकारी कर्मियों, पेंशनरों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों को मिलाकर वह संख्या दस करोड़ के पार पहुंच जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं होता है, तो लोकसभा चुनाव में भाजपा को राजनीतिक नुकसान झेलना होगा। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मी, 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है। एक कर्मी को एनपीएस में 2417 रुपये मासिक पेंशन मिली है, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मी को 4,900 रुपये प्रतिमाह की पेंशन मिली है। अगर यही कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में होते तो उन्हें प्रतिमाह क्रमशः 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये मिलते। एनपीएस में कर्मियों द्वारा हर माह अपने वेतन का दस प्रतिशत शेयर डालने के बाद भी उन्हें रिटायरमेंट पर मामूली सी पेंशन मिलती है।

एनपीएस के तहत राज्य सरकारें, अपना और कर्मचारी की सैलरी का एक तय हिस्सा पेंशन फंडिंग रेगुलेटरी डेवलेपमेंट अथॉरिटी को देती हैं। इसे बाद में कर्मचारी को पेंशन के रूप में दिया जाता है। इसके तहत पेंशन फंडिंग एडजस्टमेंट के तहत राज्य सरकारें, केंद्र से अतिरिक्त कर्ज ले सकती हैं। यह अतिरिक्त कर्ज राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का तीन फीसदी तक हो सकता है। पुरानी पेंशन योजना को दोबारा से लागू करने वाली राज्य सरकारों और केंद्र के बीच ठन गई है। जिन गैर-भाजपा शासित राज्यों ने अपने कर्मियों को पुरानी पेंशन के दायरे में लाने की घोषणा की है, उन्हें एनपीएस में जमा कर्मियों का पैसा वापस नहीं मिलेगा। केंद्र ने साफ कर दिया है कि यह पैसा पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी अथारिटी (पीएफआरडीए) के पास जमा है। नई पेंशन योजना एनपीएस के अंतर्गत केंद्रीय मद में जमा यह पैसा राज्यों को नहीं दिया जा सकता। वह पैसा केवल उन कर्मचारियों के पास जाएगा, जो इसका योगदान कर रहे हैं।

अब हर जगह मिल रही है कागज वाली स्ट्रॉ... मगर इसके कैमिकल बॉडी में ये दिक्कत कर रहे हैं!

सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए काफी कोशिश की जा रही है. अब किसी भी रेस्टोरेंट में जाइए, आपको कोई भी ड्रिंक पीने के लिए कागज वाली स्ट्रॉ दी जाती है. यहां तक कि जो पैकेट बंद ड्रिंक आ रहे है, उनके साथ भी प्लास्टिक की जगह कागज वाली स्ट्रॉ का इस्तेमाल हो रहा है. सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए इसे अच्छा कदम भी माना जा रहा है. लेकिन, इसी बीच एक ऐसे स्टडी सामने आई है, जो डराने वाली है. दरअसल, इस स्टडी में सामने आया है कि पेपर वाली स्ट्रॉ को बनाने के लिए खतरनाक कैमिकल का इस्तेमाल हो रहा है. इस कैमिकल का असर आपकी हेल्थ पर भी पड़ रहा है और ऐसे में इस पेपर स्ट्रॉ को भी हेल्थ के लिए ठीक नहीं माना जा रहा है. तो जानते हैं कि आखिर इस स्ट्रॉ से जुड़ी स्टडी में क्या कहा गया है और किस आधार पर इसका इस्तेमाल गलत माना जा रहा है...

स्टडी में क्या कहा गया है?

रिपोर्ट के अनुसार कुछ रिसर्चर्स ने एक स्टडी की है, जिसमें सामने आया है कि पेपर स्ट्रॉ से कोई भी ड्रिंक पीना नुकसानदायक हो सकता है. इस स्टडी में दावा किया गया है कि इन स्ट्रॉ में कुछ टॉक्सिक कैमिकल होते हैं, जो लोगों के लिए खतरनाक होने के साथ ही दूसरे जीवों और पर्यावरण के लिए भी खतरा पैदा कर सकती हैं. स्टडी में कहा गया है कि जब कई स्ट्रॉ पर रिसर्च की गई तो सामने आया कि कागज और बांस की बनी स्ट्रॉ में पॉली- और पेरफ्लूरोएल्काइल पदार्थ (पीएफएएस) मिला है.

बता दें कि पीएफए के लिए कहा जाता है कि ये काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं और इंसानों की हेल्थ के लिए खतरनाक है. स्टडी के अनुसार, बाजार में पेपर स्ट्रॉ बना रही करीब 20 में से 18 कंपनियों की स्ट्रॉ में शामिल है. हालांकि, अभी ये सामने नहीं आया है कि क्या ये पीएफए उस ड्रिंक में भी घुल जाता है.

ये कैमिकल ऐसे होते हैं कि ये लंबे समय तक आपके शरीर में रह सकते हैं. इस कैमिकल की वजह से शरीर में थायराइड, कॉलेस्ट्रॉल बढ़ने, लिवर में दिक्कत, किडनी में कैंसर, जन्म के समय कम वजन, टीकों का असर कम होना जैसी दिक्कत हो सकती हैं. वहीं, इस स्टडी में ये भी सामने आया है कि किसी भी स्टील स्ट्रॉ में पीएफएएस निशान नहीं पाया गया और वो सेफ हैं. बता दें कि बड़ी मात्रा में कागज की स्ट्रॉ में पीएफएएस की उपस्थिति वॉटर कोटिंग की वजह से है.

रिफाइंड शुगर की जगह चाय में मिलाएं गुड़, 5 कारणों से सर्दियों में फायदेमंद है गुड़ की चाय

अक्सर हम चाय में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, परंतु आपको यह मालूम होना चाहिए कि रिफाइंड शुगर सेहत के लिए कितनी हानिकारक हो सकती है। इसलिए सर्दी में चाय में पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ को शामिल करने की सलाह दी जाती है। इससे आपके शरीर को कई फायदे मिल सकते हैं। विंटर सीजन और चाय का कॉम्बिनेशन सदियों से सबका पसंदीदा बना हुआ है। सर्दी के मौसम में यदि किसी से पूछा जाए कि आप क्या पियेंगे, तो सबसे पहले जवाब आता है चाय। हालांकि, हम सभी को सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों तथा संक्रमण से लड़ने के लिए अपने शरीर को तैयार रखने की आवश्यकता होती है। इसमें जिसमें विंटर सुपरफूड्स हमारी मदद कर सकते हैं। इन्ही विंटर सुपरफूड्स में एक है गुड़। इसी गुड़ को चाय में मिलाकर आप अपनी नियमित चाय को और भी ज्यादा हेल्दी बना सकते हैं। जानना चाहती हैं कैसे, तो बस इसे अंत तक पढ़ती रहें। पोषक तत्वों से भरपूर गुड़ का सेवन, सर्दियों में खासतौर से फायदेमंद होता है। सालों से मेरे घर में गुड़ की चाय बनती आ रही है, खासकर सर्दी के मौसम में मेरी मां गुड़ की चाय बनाया करती हैं। तो क्यों न इसे आप भी आजमा कर देखें। इस सर्दी अपनी पसंदीदा चाय में गुड़ के साथ जोड़ें सेहत का तड़का। तो चलिए जानते हैं गुड़ की चाय के फायदे साथ ही जानेंगे इन्हें बनाने का सही तरीका।

शरीर को गर्म रखती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है- गुड़ कई महत्वपूर्ण मिनरल्स और विटामिन जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फोरस आदि से भरपूर होता है। ये सभी पोषक तत्व शरीर को गर्म रखने के साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। मजबूत इम्युनिटी शरीर को संक्रमण से बचाता है और बीमारियों के खतरे को भी कम कर देता है। इनका सेवन ठंड में आपके शरीर के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है।

सर्दी और फ्लू से प्रोटेक्ट करे- पब मेड सेंट्रल के अनुसार गुड़ शरीर में गर्मी पैदा करता है, इसके साथ ही बॉडी इम्युनिटी को भी बढ़ावा देता है। मजबूत इम्युनिटी सर्दी-खांसी का कारण बनने वाले कीटाणुओं के प्रभाव को कम कर देता है। यह आम सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करता है।

ब्लड को प्यूरीफाई कर लिवर टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है- नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, गुड़ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट ब्लड को प्यूरीफाई कर लीवर से टॉक्सिक पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। वहीं इसके नियमित सेवन से हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है। जब शरीर से बॉडी टॉक्सिंस पूरी तरह से बाहर निकल आते हैं, तो शरीर को स्वस्थ रहने में मदद मिलती है।

वेट लॉस प्रमोट करे- गुड़ में मौजूद पोषक तत्व इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित करने में मदद करते हैं। यह मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे वजन घटाने में मदद मिलती है। चाय में मिठास घोलने के लिए रिफाइंड शुगर की जगह गुड़ का सेवन, कई रूपों में अधिक प्रभावी साबित हो सकता है और यह सेहत को भी बढ़ावा देता है।

ऊर्जा शक्ति बनी रहती है- चीनी के विपरीत, गुड़ एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब है कि यह धीरे-धीरे टूटता है और तुरंत रक्तप्रवाह में अवशोषित नहीं होता है। ऐसे में यह शरीर में धीरे-धीरे ऊर्जा जारी करता है और शरीर को लंबे समय तक एनर्जेटिक रहने में मदद करता है।

क्या अकसर फट जाती है गुड़ वाली चाय?- गुड़ की चाय बनाते समय कभी-कभी दूध फट जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गुड़ को प्रोसेस करने के लिए कई बार केमिकल्स का उपयोग किया जाता है। इसीलिए जब आप गुड़ को दूध के साथ उबालते हैं, तो गुड़ में मौजूद केमिकल्स दूध के साथ रिएक्ट करते हैं और चाय फट जाती है।

कंधों में जकड़न होती है तो करें ये स्ट्रेच एक्सरसाइज, मिलेगा आराम

अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सर्दियों में पता नहीं उनका वजन कैसे बढ़ जाता है, जबकि वे तमाम हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार ही लेते हैं। क्या आपको भी यही लगता है कि सर्दियां अपने साथ बढ़े हुए वजन की सौगात लेकर आती है? असल में जाड़े का मौसम अपने साथ बहुत सारी जायकेदार खाने की चीजें तो लाता है, साथ ही आलस भी दे जाता है। दोपहर की गुनगुनी धूप में मूंगफली चबाना या रात को रजाई में बैठकर गरमागरम गाजर का हलवा खाना भला किसे अच्छा नहीं लगता है। पर, इन जायकों का आनंद लेते-लेते पता ही नहीं चलता कि वजन कब बेकाबू हो गया। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं, जो सर्दियों में आपका वजन बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर्दियों की शुरुआत में ही अपनी जीवनशैली और खानपान में जरूरी बदलाव करके इस समस्या से बचा जा सकता है। गरिष्ठ भोजन के सेवन के अलावा ऐसे अन्य बहुत से कारण हैं जो ठंडे मौसम में वजन बढ़ा सकते हैं।

दिन छोटे होना

गार्मियों के मौसम में सूरज देर से छिपता है, लेकिन सर्दियों में दिन काफी छोटे होते हैं क्योंकि सूर्यास्त काफी जल्दी हो जाता है। नतीजतन, दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं। इसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और सुस्ती का अहसास बहुत जल्दी होने लगता है।

कम शारीरिक गतिविधियां

ठंडे मौसम में शरीर का तापमान भी नीचे गिरने लगता है, जिससे सर्दी का एहसास होता है। ऐसे में सिर्फ गर्माहट में रहने पर ही बेहतर महसूस होता है। जिस वजह से शारीरिक गतिविधियां बहुत ज्यादा सीमित हो जाती हैं और शरीर में अतिरिक्त कैलोरी जमा होने लगती हैं।

पानी कम पीना

ठंडे मौसम में प्यास कम लगती है, इसलिए सामान्य से कम पानी पिया जाता है। असल में हमारा शरीर भूख और प्यास के संकेतों में अंतर नहीं कर सकता, इसलिए प्यास लगने पर भी अकसर भूख का ही एहसास होता है और हम पानी पीने की बजाय कुछ खा लेते हैं।

सूरज की कम रोशनी

पर्याप्त मात्रा में सूरज का प्रकाश ना मिलने का सीधा असर हमारे मूड पर पड़ता है और शरीर में सेराटोनिन नामक हैप्पी हार्मोन का स्तर नीचे जाने लगता है। जिसे दोबारा सामान्य स्तर तक लाने के लिए मीठा और कम्फर्ट फूड खाने की तीव्र इच्छा होती है। सूरज की रोशनी की कमी सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की समस्या भी पैदा कर सकती है, जिससे शरीर में सुस्ती, उदासी और आलस महसूस होने लगता है।

गरिष्ठ भोजन का सेवन

ठंडे मौसम में शरीर को सुचारू रूप से काम करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस मौसम में घी और मीठे का सेवन बढ़ जाता है। वैसे भी ठंडे मौसम में तले हुए पकवान और मिठाइयां लोगों को ज्यादा भाते हैं, जो धीरे-धीरे करके वजन बढ़ा देते हैं।

कैसे रखें वजन पर नियंत्रण

माना सर्दियों में बहुत सुस्ती आती है, लेकिन अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर आसानी से वजन को नियंत्रण में रखा जा सकता है।

संतुलित आहार का सेवन

जंक फूड और तले-भुने भोजन की बजाय घर के बने पौष्टिक और हल्के आहार का सेवन करें। समोसे, कचौड़ी, बर्गर और ऐसे ही तमाम चीजों का लुत्फ कभी-कभी ही उठाएं। साथ ही खाने की मात्रा का भी खयाल रखें।

व्यायाम है जरूरी

गिरते तापमान के बीच रजाई की गर्माहट छोड़कर बाहर निकलकर कसरत करने की हिम्मत नहीं होती है। पर, घर पर हल्का-फुल्का व्यायाम किया जा सकता है। चाहें तो दोपहर के समय पार्क में टहलने चले जाएं। विटामिन-डी मिलने के साथ-साथ सुस्ती भी भाग जाएगी।

भरपूर पानी पीएं

शरीर में पानी की कमी मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देती है और वजन बढ़ने लगता है। ठंड में भी शरीर में पानी की कमी ना होने दें। यदि हर बार पानी पीने का मन ना करे तो वेजिटेबल सूप, फ्रूट जूस, बिना चीनी वाला नीबू पानी, मसाला चाय, हल्दी वाला दूध और नारियल पानी जैसे पौष्टिक पेय पदार्थों का सेवन करें।

लें भरपूर नींद

बिना वजह देर रात तक जागे रहने से भूख के लिए जिम्मेदार हार्मोन प्रभावित होते हैं और असमय खाना खाने की इच्छा होती है। सही समय पर सोने की आदत डालें।

कैफीन और एल्कोहल से दूरी

कुछ लोग सर्दियों में गर्माहट के लिए कैफीन और एल्कोहल का अत्यधिक सेवन करने लगते हैं, जो सेहत खराब करने के साथ-साथ शरीर में अतिरिक्त कैलोरी भी बढ़ा देते हैं। इससे कुछ देर के लिए रक्तचाप तेज हो जाता है और गर्मी का एहसास होता है। पर, असर खत्म होते ही फिर से सर्दी लगने लगती है। इसलिए इनसे परहेज करें।

बाहर खाना खाते समय

किसी होटल में या शादी-ब्याह में खाना खाते समय पहले सलाद खाएं और बाद में किसी और व्यंजन का सेवन करें ताकि वह ज्यादा ना खाया जा सके।

सही समय पर मूली खाने से नहीं बनेगी गैस, जानिए किन लोगों को करना चाहिए परहेज?

सर्दियों में सलाद की प्लेट में मूली भी शामिल हो जाती है। ये खाने में काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसे खाने से इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है और पाचनतंत्र बेहतर तरीके से काम करने लगता है। मूली को रोजाना खाने से किडनी से लेकर लीवर तक हेल्दी रहता है। गुणों से भरपूर मूली के साथ बस एक समस्या कई बार लोगों को परेशान करती है और वो है मूली खाने के बाद गैस बनना। ऐसा तब होता है जब आप गलत समय पर इसे खाते हैं। आयुर्वेद के मुताबिक मूली खाने के लिए आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए, यहां जानिए इसे खाने का सही समय और किन लोगों को इससे परहेज करना चाहिए।

मूली से किसे करना चाहिए परहेज?

मूली की तासीर बहुत गर्म होती है। इसके अलावा इसमें तीनों दोषों को शांत करने की शक्ति होती है। अगर किसी व्यक्ति को भूख ठीक लगती है या भूख नहीं लगती, तो इन लोगों को मूली से परहेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे गैस्ट्रिक समस्याएं हो सकती हैं।

इस समय ना खाएं

मूली का स्वाद हल्का मीठा और तीखा होता है। सर्दियों के दिनों में इसे खाने से खूब फायदा मिलता है। मूली को धूप में आराम से बैठकर खाना सबसे अच्छा है। हालांकि, इसे कभी भी खाली पेट नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा रात में मूली खाना अच्छा नहीं है।

किस समय खाएं मूली?

मूली खाने का सबसे अच्छा समय रहेगा आप इसे दोपहर में खा लें। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि लंच से पहले इसे खाएं। इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा और न ही खाने के बाद गंदी डकार आएगी।

कैसे खाएं मूली?

मूली को कई तरीकों से खा सकते हैं। अगर आप कच्ची मूली नहीं खा सकते, तो इसका स्टफ पराठा या सब्जी बना लें। मूली का अचार भी काफी अच्छा लगता है।

न सुपरफूड्स को खाकर बूस्ट होगी इम्यूनिटी, ठंड के मौसम में रहेंगे फिट

सर्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है। ऐसे में सर्दी और खांसी से जुड़ी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। अक्सर लोगों को ज्यादा ठंडे मौसम के कारण सिरदर्द, लगातार खांसना, छींकना और नाक बहने से परेशान करने वाला होता है। सर्दी के मौसम में बढ़ते फलू के डर से बचने के लिए इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। यहां आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे सूपरफूड्स के बारे में, जो आपकी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेंगे। अच्छी बात यह है कि इम्यूनिटी बूस्ट के लिए सुपरफूड मानी जाने वाली सभी चीजें घर में आसानी से मिल जाएंगी।

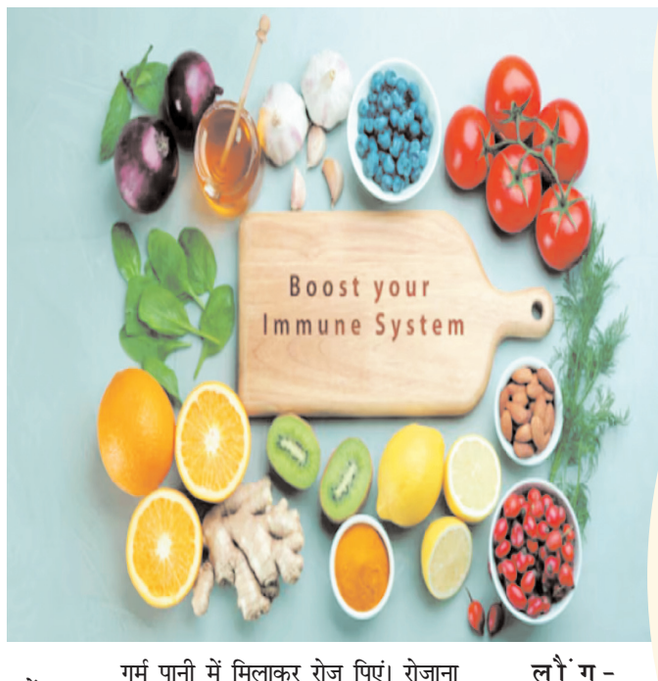

सौंफ- सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। ये पाचन में मदद करती हैं। इसी के साथ गले की खराश को कम करने और खांसी को दूर करने में भी ये फायदेमंद होती है। सर्दी के मौसम में आप सौंफ की चाय या सौंफ वाला पानी पी सकते हैं। इसे आप खाने के आधे घंटे बाद पी सकते हैं।

शहद- शहद कई तरह के औषधीय गुणों से भरपूर है। ये कई बीमारियों के इलाज में फायदेमंद हो सकता है। इस आप गर्म पानी में मिलाकर रोज पिएं। रोजाना सुबह इसे पीने से शरीर के टॉक्सिन को बाहर निकलने में मदद मिलती है।

हल्दी- हल्दी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी इंफ्लैमेटरी एंटीवायरस और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं। इसका इस्तेमाल खांसी और सर्दी के इलाज में किया जाता है। सुबह हल्दी का पानी या फिर रात को सोते समय हल्दी वाला दूध पी सकते हैं।

लौंग- लौंग में यूजेनॉल होता है, जिसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट होते हैं, जो शरीर को फ्री रेडिकल्स के खिलाफ बचाने में मदद कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी को मजबूत करने में भी मदद कर सकता है।

हेयर कॉम्ब करने का यह है सही तरीका, तुरंत सुलझ जाएंगे बाल...साथ ही होंगे ये फायदे

अपने बालों को अच्छे से संवारने के लिए उनमें कंघी करना बेहद जरूरी है. लोग अक्सर ऊपर से नीचे की और कंघी करते हैं लेकिन क्या आपको पता है अगर आप नींचे से ऊपर की ओर कंघी करेंगे तो इससे आपको कई सारे फायदे मिलते हैं. आज हम आपको इसके फायदे के बारे में बताएंगे. इंस्टाग्राम पेज हेयर सेवियर्स के मुताबिक बालों को नीचे से ऊपर की ओर धीरे से ब्रश करने से बाल हेल्दी और सेहतमंद होता है. अगर आप नीचे की और से बाल झाड़ेंगे तो बाल की गांठें तुरंत सुलझ जाती है. इससे बाल में खिंचाव कम होता है. साथ ही साथ टूटने और दोमुंहे बाले से भी छुटकारा मिल जाता है.

उलझे हुए बाल की रोकथाम- अगर आपके बाल काफी ज्यादा उलझे हुए रहते हैं या उसमें गांठ पड़ जाती है तो आप इस तरीके से कंघी कर सकते हैं.

बाल में खींचाव

हेयर ब्रश को नीचे से ऊपर की बाल झाड़ने से तुरंत सुलझ जाते हैं. उसमें उलझे हुए बाल झड़ने लगते हैं.

कम टूटना

गीले होने पर बालों के टूटने की संभावना अधिक होती है। जब बाल सूखे हों तो नीचे से शुरू करने से उनका टूटना कम हो जाता है, जिससे ब्रश करने का अनुभव अधिक सहज और स्वस्थ होता है.

खोपड़ी पर कोमल

नीचे से धीरे से ब्रश करना खोपड़ी के लिए दयालु होता है, अनावश्यक जलन को रोकता है. यह खोपड़ी के रक्त परिसंचरण को भी उत्तेजित करता है, जिससे बालों के समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलता है.

बालों की संरचना को बनाए रखता है

बालों के बढ़ने की दिशा में ब्रश करने से बालों की प्राकृतिक संरचना और संरेखण को बनाए रखने में मदद मिलती है. यह साफ-सुथरा दिखने में योगदान दे सकता है और फ्रिज़ के जोखिम को कम कर सकता है.

बाल में गांठ पड़ जाती है. इसे आप कंघी से ही ठीक कर सकते हैं.

बाल कम खींचना

नीचे से ब्रश करने से बालों को जड़ों से उखाड़ने की संभावना कम हो जाती है, जिससे असुविधा हो सकती है और संभावित रूप से समय के साथ

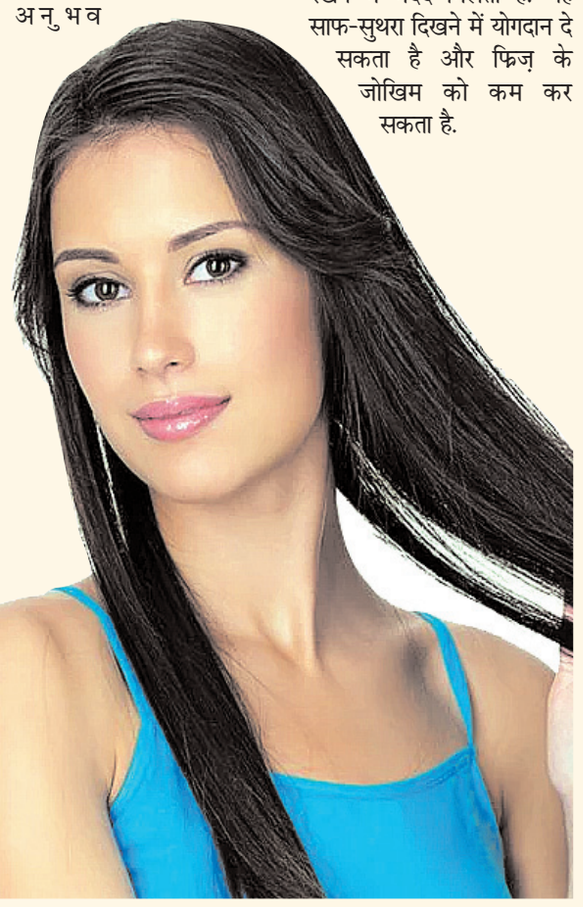

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

विपक्षी दलों ने संसद में आगे की रणनीति पर चर्चा की

नईदिल्ली। विपक्षी दलों के नेताओं ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार द्वारा लाए जाने वाले विधेयकों तथा महंगाई, बेरोजगारी और जनहित के अन्य मुद्दों पर आगे की रणनीति को लेकर मंगलवार को चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के संसद भवन स्थित कक्ष में हुई बैठक में, खरगे के अलावा लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन, द्रमुक के नेता तिरुची शिवा, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा और समाजवादी पार्टी के एसटी हसन तथा कुछ अन्य विपक्षी नेता शामिल हुए। कांग्रेस ने सोमवार को कहा था कि वह संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में तीन आपराधिक कानूनों के स्थान पर लाए गए विधेयकों, निर्वाचन आयुक्त विधेयक तथा तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन के कदम का विरोध करेगी।

कांग्रेस ने चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा

नईदिल्ली। विधानसभा चुनावों में हार का ठीकरा कांग्रेस ने एक बार फिर ईवीएम पर फोड़ दिया है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भाजपा की जीत को ईवीएम की जीत बताया है तो दूसरी ओर भाजपा ने सवाल किया है कि तेलंगाना में किसकी जीत हुई है। देखा जाये तो ईवीएम पर सवाल उठा कर विपक्ष भारतीय निर्वाचन आयोग की साख पर सवाल उठा रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग की दुनिया भर में प्रतिष्ठा है और विभिन्न देशों में चुनावों के दौरान संयुक्त राष्ट्र की ओर से भारतीय निर्वाचन आयोग को पर्यवेक्षक के तौर पर भी तैनात किया जाता है। यही नहीं, चुनाव प्रक्रिया के दौरान हजारों की संख्या में अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का कुशलता से निर्वहन किया लेकिन उनका उत्साह वर्धन करने और उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। विपक्ष अपनी कमियों पर चिंतन करने की बजाय, विपक्ष अपनी गलतियों पर चर्चा करने की बजाय, विपक्ष अपनी नाकामियों को स्वीकारने की बजाय ईवीएम पर लगातार सवाल उठा रहा है।

जब कांग्रेस जीतती है तो सब कुछ ठीक रहता है : गिरिराज

नईदिल्ली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के इस दावे पर प्रतिक्रिया में कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि यह घटना नई नहीं है और जब भी विपक्ष चुनावी लड़ाई में हारता है, तो वे ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। गिरिराज सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा, यह कोई नई बात नहीं है। विपक्ष ईवीएम पर तभी सवाल उठाता है जब वे चुनाव हार जाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि विधानसभा चुनावों में जीत पर विपक्ष हिमाचल प्रदेश या तेलंगाना की तरह इसी तरह के सवाल क्यों नहीं उठाता। भाजपा नेता ने कहा कि उन्होंने हिमाचल प्रदेश चुनाव या तेलंगाना चुनाव के दौरान ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए? जब वे जीतते हैं तो सब कुछ ठीक होता है, जब वे हारते हैं तो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। सिंह ने दावा किया कि लोगों ने उन्हें वोट क्यों नहीं दिया, इस पर गौर करने के बजाय विपक्ष ईवीएम पर सवाल उठाता है।

मप्र कांग्रेस प्रमुख पद से इस्तीफा दे सकते हैं कमलनाथ

भोपाल। विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के दो दिन बाद कमलनाथ के मंगलवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने की संभावना है और वह मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के पद से अपना इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कांग्रेस नेतृत्व इस बात से नाराज है कि कमलनाथ पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से नहीं मिल रहे हैं, बल्कि शर्मनाक हार के एक दिन बाद सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर रहे हैं। कमलनाथ ने आज कहा है कि हम निर्वाचित और गैर-निर्वाचित विधायकों के साथ चर्चा कर रहे हैं और परिणाम का विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ विधायक मुझसे मिले हैं और उनमें से एक ने मुझे बताया कि उन्हें अपने गांव में केवल 50 वोट मिले हैं। यह कैसे संभव है?...उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल सिर्फ माहौल बनाने के लिए किए जाते हैं।

तेलंगाना कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर बगावत

हैदराबाद। तेलंगाना चुनावों में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। इस जीत के साथ ही पांच राज्यों में से एक जगह पार्टी अपनी सत्ता बनाने में सफल रही है। सत्ता बनाने के साथ ही राज्य में बगावत के सुर भी मजबूत होने लगे है। तेलंगाना में शानदार जीत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी में बगावत देखने को मिल रही है। ये बगावत मूल रूप से राज्य के मुख्यमंत्री पद को लेकर हो रही है। माना जा रहा है कि राज्य के कई बड़े नेताओं ने रेवंत रेड्डी के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के चीफ रेवंत रेड्डी के नाम पर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मुख्यमंत्री के तौर पर मुहर लगाने से इनकार कर दिया है। वरिष्ठ उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क ने भी मुख्यमंत्री के पद पर अपनी दावेदारी पेश की है। हालांकि इस संबंध में अबतक पार्टी ने कोई बयान जारी नहीं किया है। बता दें कि 119 सीटों वाले तेलंगाना में कांग्रेस ने 63 सीटों पर कब्जा जमाया है।

इंडिया गठबंधन की आज होने वाली बैठक टली

ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अखिलेश यादव ने बनाई थी दूरी

नईदिल्ली। विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के कुछ घटक दलों के प्रमुख नेताओं की अनुपलब्धता के चलते बुधवार को होने वाली गठबंधन की प्रस्तावित बैठक फिलहाल स्थगित कर दी गई है। गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस के सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर इस गठबंधन की 'अनौपचारिक समन्वय बैठक' होगी जिसमें इस गठबंधन में शामिल पार्टियों के संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। सूत्रों का कहना है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रमुक के नेता एमके स्टालिन चक्रवात के कारण पैदा हुए हालात के चलते बैठक में शामिल नहीं हो सकते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं तथा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार में वैवाहिक कार्यक्रम है। ऐसे में आगे की तिथि के लिए बैठक को स्थगित किया गया है।

यह बैठक ऐसे समय होने वाली थी जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हालिया विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस ने तेलंगाना में जीत दर्ज की है। अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का मुकाबला करने के लिए 26 विपक्षी दलों ने 'इंडिया' गठबंधन बनाया है। 'इंडिया' गठबंधन की अब तक तीन बैठक पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो चुकी हैं। आपको बता दें कि गठबंधन के घटक दलों के नेताओं की पिछले दिनों मुंबई में हुई बैठक में गठबंधन के भविष्य के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए 14 सदस्यीय समन्वय समिति का गठन किया गया था। समन्वय समिति विपक्षी गठबंधन की शीर्ष निर्णय लेने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगी।

समाजवादी पार्टी (सपा) के प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने मंगलवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बुधवार को दिल्ली में होने वाली विपक्ष के इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस (इंडिया) की बैठक में जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने का कोई कार्यक्रम नहीं है। पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव या राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा अधिकृत कोई अन्य नेता बैठक में शामिल होंगे।

माना जा रहा है कि कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की बैठक को बुलाने का एक तरफा फैसला लिया। कांग्रेस की ओर से इसको लेकर किसी भी सहयोगी दलों से राय नहीं ली गई। यही कारण है कि इन नेताओं ने इस बैठक से दूरी बनाई। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई, जब तीन बड़े राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसे हार का सामना करना पड़ा। इंडिया गठबंधन के कई दलों का कहना है कि कांग्रेस ने इन चुनाव में हमारी नहीं सुनी। हमें अपमानित करने की कोशिश की गई। इन चुनाव के दौरान अपने सहयोगी दलों का भी कांग्रेस की ओर से साथ नहीं लिया गया। यही कारण है कि इंडिया गठबंधन के नेताओं में नाराज की बढ़ गई है। कुछ तो इसे कांग्रेस का अहंकार बता रहे हैं।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सोमवार को दावा किया कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नतीजे हिंदी पट्टी में जबरदस्त कांग्रेस विरोधी भावना को दर्शाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रमुख सहयोगियों ने 'इंडिया' गठबंधन के नेतृत्व के लिए जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के सुप्रीमो जैसे ''विश्वसनीय चेहरे'' पर जोर दिया।

बैठक में ममता के न आने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी

ममता बनर्जी के बैठक में शामिल होने से इनकार करने पर कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी भड़क गए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, उसका घमंड चुनाव से पहले भी ऐसा ही था। पांच राज्यों में चुनाव थे, लेकिन उसने भाजपा को हराने के लिए लोगों से विपक्षी पार्टियों को वोट देने की अपील तक नहीं की। बैठक को लेकर ममता बनर्जी के बयान पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सफाई पेश की। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन में सभी साथ है। हम यहां किसानो से लेकर महिलाओं की सुरक्षा जैसे अन्य कई मुद्दों से लड़ने के लिए हैं। हम इस मुद्दों को देखेंगे और ठीक करने की कोशिश करेंगे। हम बैठक के शीघ्र आयोजन के लिए हर संभव योजना करेंगे।

कांग्रेस को नीतीश ने दिया मैसेज

पांच राज्यों का चुनाव आया तो इस इंडी एलायंस के सबसे बड़े और राष्ट्रीय दल कांग्रेस ने गठबंधन को दरकिनार कर अकेले प्रत्याशी उतारे। हिंदीभाषी तीन राज्यों में कांग्रेस की करारी शिकस्त का चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस ने इंडी एलायंस का रुख किया और छह दिसंबर को दिल्ली में बैठक रख ली। ममता बनर्जी, अखिलेश यादव के दूरी बनाने की खबर के साथ ही इस गठबंधन के संयोजक की जगह सूत्रधार कहे गए नीतीश कुमार ने भी दूरी बना ली। इस दूरी के साथ नीतीश कुमार ने कांग्रेस को दो तरह से मैसेज दिया। कैबिनेट बैठक में हाजिरी के बावजूद दिल्ली नहीं जाने का फैसला कर जहां गैर-मौखिक मैसेज दिया है, वहीं उनके करीबी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सीएम नीतीश के मन की बात खुलकर कह दी है। उन्होंने कहा- हर चुनाव, चाहे वह एक प्रदेश में हो या अनेक राज्यों में, कुछ स्पष्ट संदेश देता है। पांच राज्यों में से चार राज्यों से स्पष्ट संदेश दिख रहा है कि इंडी एलायंस के सभी घटक दलों को ज्यादा समझदारी से काम करना होगा। इस चुनाव मे भी इंडी एलायंस एकजुट होकर चुनाव नही लड़ा था। हमलोग शुरू से कहते हैं कि आपस की समझदारी बननी चाहिए। सारे विपक्षी दल एकजुट हो जाते हैं तो भाजपा परास्त हो जाती। एकजुट नहीं होने पर भाजपा परास्त नहीं होती है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और इन चुनावों में कांग्रेस को ज्यादा घाटा हुआ है। दिल्ली में खुले मन से सभी को बैठकर सोचना चाहिए कि चुनावों में साझा उम्मीदवार हों। हमलोग उम्मीद करते हैं कांग्रेस अब आगे बढ़कर सभी क्षेत्रीय दलों को उच्चित समान देकर, साथ लेकर चलेगी।

प्रधानमंत्री का विपक्ष पर निशाना

वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें: मोदी

नई दिल्ली। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को तीन राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद से सत्ता के गलियारे में भारी गहमा-गहमी मची हुई है। एक तरफ कांग्रेस में निराशा है तो वहीं दूसरी ओर भाजपा में जीत के प्रति भारी उत्साह है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी की जीत से उत्साहित होकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया है। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों से अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता के साथ शांति रहना चाहिए क्योंकि लोग उनके विभाजनकारी एजेंडे से अवगत हैं।

पीएम मोदी ने मंगलवार को सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर किये एक पोस्ट में कहा, वे अपने अहंकार, झूठ, निराशावाद और अज्ञानता से खुश रहें। लेकिन लोग उनके विभाजनकारी एजेंडे से सावधान रहें। 70 साल की पुरानी आदत इतनी आसानी से नहीं जा सकती। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में भी ऐसी कई मंदी के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा, लोगों में इतनी समझदारी है कि उन्हें आगे कई और मंदी के लिए तैयार रहना होगा।

पीएम मोदी द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी हार के लिए कांग्रेस समर्थकों द्वारा कथित तौर पर बनाए गए बहानों को सूचीबद्ध किया गया है। जिसमें मतदाताओं को उनकी पसंद के लिए दोषी ठहराया जाता है। चुनाव परिणाम के दिन अपने विजय भाषण में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि अगर वे एक मंच पर एक साथ आते हैं और चाहे कितनी भी अच्छी फोटो क्यों न खींची जाए, वे लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करते हुए कहा, ये चुनाव परिणाम कांग्रेस और उसके अहंकारी गठबंधन दलों के लिए भी एक सीखने का अनुभव है। अगर

कुछ वंशवादी दल एक मंच पर एक साथ आते हैं तो चाहे कितनी भी अच्छी फोटो खींची जाए। आप देश का विश्वास नहीं जीत सकते। उन्होंने कहा, देश का दिल जीतने के लिए आपको देश की सेवा करने की इच्छा दिखाने की जरूरत है और ये अहंकारी गठबंधन सहयोगी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं दिखाते हैं।

एमएसपी को लेकर काम कर रही मोदी सरकार

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने मंगलवार को लोकसभा में कहा कि कृषि सुधारों को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट संप्रग सरकार के दौरान आई थी लेकिन नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली राजग सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) उत्पाद लागत से 50 प्रतिशत अधिक तय किया गया है। तोमर ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग ने 201 सिफारिशें की थीं। उन्होंने कहा कि इनमें से राजग सरकार 100 पर काम कर रही है, लेकिन मुख्य सिफारिश एमएसपी पर थी। स्वामीनाथन ने कहा था कि लागत पर 50 प्रतिशत मुनाफा जोड़कर एमएसपी घोषित की जानी चाहिए। नरेन्द्र मोदी सरकार आई तो आयोग की सिफारिश पर काम शुरू हो गया। आज लागत दर पर 50 प्रतिशत लाभ जोड़कर एमएसपी घोषित की जाती है।

खेल
प्रमुख समाचार

टी20 में भारतीय महिला टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से

नईदिल्ली। भारतीय महिला क्रिकेट टीम पिछले कुछ अर्से के अच्छे प्रदर्शन से प्रेरणा लेकर इंग्लैंड के खिलाफ द्विपक्षीय रिकॉर्ड बेहतर करने के इरादे से बुधवार से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 श्रृंखला में उतरेगी। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत ने टी20 प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन किया है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा भारत ने बांग्लादेश में 2-1 से जीत दर्ज की और दक्षिण अफ्रीका तथा वेस्टइंडीज के खिलाफ त्रिकोणीय श्रृंखला के फाइनल में पहुंची।

दूसरी ओर दुनिया की दूसरे नंबर की टीम इंग्लैंड श्रीलंका से 1-2 से मिली पराजय को भुलाकर नये सिरे से शुरूआत करने उतरेगी। दुनिया की चौथे नंबर की टीम भारत का इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 श्रृंखलाओं में रिकॉर्ड खराब रहा है। मेजबान टीम इसे दुरूस्त करने के इरादे से उतरेगी। इंग्लैंड के खिलाफ भारत में नौ मैचों में से भारत ने सिर्फ दो जीते हैं। आखिरी जीत पांच साल पहले मार्च 2018 में मिली थी जब ब्रेबोर्न स्टेडियम पर आठ विकेट से इंग्लैंड को हराया था। इंग्लैंड के खिलाफ अब तक कुल 27 मैचों में से भारत ने सिर्फ सात जीते हैं। भारतीय महिला टीम ने आखिरी बार अपनी सरजमीं पर टी20 मैच मार्च 2021 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लखनऊ में जहीता था। उसके बाद से भारत अपने देश में चार मैच हार चुका है और एक टाई रहा। भारत ने घरेलू 50 टी20 मैचों में से सिर्फ 19 जीते हैं, 30 हारे और एक टाई रहा। भारत और इंग्लैंड दोनों ने पिछले टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। अगला टूर्नामेंट सितंबर अक्टूबर 2024 में होना है और उसकी तैयारी का यह सुनहरा मौका है। दीप्ति शर्मा ने भारत के लिये 16 मैचों में 19 विकेट लिये हैं जबकि बल्लेबाजी में हरमनप्रीत ने 13 टी20 में 323 रन बनाये हैं। जेमिमा रौड्रिग्स ने 16 मैचों में 342 रन बनाये हैं जबकि स्मृति मंधाना ने 15 मैचों में सर्वाधिक 369 रन का योगदान दिया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स और निफ्टी नए ऑल-टाइम हाई पर बंद

नईदिल्ली। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जानता पार्टी की जोरदार जीत से उत्साहित शेयर बाजार लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन में तेजी के साथ बंद हुआ। बाजार के बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी मंगलवार को अपने ऑल टाइम हाई लेवल पर बंद हुए। अमेरिका के मुख्य आर्थिक आंकड़े जारी होने से पहले वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद भारतीय शेयर बाजार में तूफानी तेजी देखी गई। तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स आज 431.02 अंक या 0.63 अंक की छलांग के साथ 69,296.14 अंक पर बंद हुआ। यह सेंसेक्स का आज तक का सबसे हाई लेवल है। सेंसेक्स की 20 कंपनियों के शेयर जहां ग्रीन निशान में बंद हुए, वहीं दस के शेयर गिरावट में बंद हुए। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी-50 भी 168.30 अंक 0.81 प्रतिशत की बढ़त लेकर 20,855.10 अंक के स्तर पर बंद हुआ, जो इसका नया रिकॉर्ड लेवल है।

इसरो ने चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल को पृथ्वी के आसपास की कक्षा में स्थापित किया

नईदिल्ली। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल को एक अनोखे प्रयोग के तहत चंद्रमा के आसपास की एक कक्षा से पृथ्वी के आसपास की एक कक्षा में स्थापित किया है। चंद्रयान-3 मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के समीप सॉफ्ट लैंडिंग करना और लैंडर 'विक्रम' तथा रोवर 'प्रज्ञान' पर उपलब्ध उपकरणों का इस्तेमाल कर नए-नए प्रयोग करना था। इसरो ने एक बयान में कहा, ''चंद्रयान-3 मिशन के उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल कर लिया गया है।'' इसमें कहा गया है कि प्रणोदन मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट (जीटीओ) से लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की अंतिम ध्रुवीय गोलाकार कक्षा तक पहुंचाना और लैंडर को अलग करना था।

भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा : एसएंडपी

नईदिल्ली। भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और वित्त वर्ष 2026-27 में देश की जीडीपी वृद्धि सात प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने मंगलवार को यह बात कही। 'ग्लोबल क्रेडिट आउटलुक 2024' में एसएंडपी ने मार्च 2024 (2023-24) तक वित्त वर्ष में 6.4 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि देखी, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 7.2 प्रतिशत थी। रेटिंग एजेंसी के अनुसार, वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष (2024-25) में 6.9 प्रतिशत पर पहुंचने से पहले 6.4 प्रतिशत बनी रहेगी और 2026-27 में सात प्रतिशत पर पहुंच जाएगी। एजेंसी ने कहा हम वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की वृद्धि दर सात प्रतिशत तक पहुंचते हुए देख रहे हैं। भारत 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है।

सर्विस सेक्टर की रफ्तार पड़ी सुस्त

नईदिल्ली। भारत के सेवा क्षेत्र की गतिविधियां नवंबर में एक साल के निचले स्तर पर पहुंच गईं। नए आर्डर मिलने और काम पूरा करने की धीमी रफ्तार के कारण यह गिरावट आई है। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित एसएंडपी ग्लोबल भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक नवंबर में एक साल के निचले स्तर 56.9 पर पहुंच गया। यह अक्टूबर में 58.4 था। मासिक आधार पर गिरावट के बावजूद, विस्तार की दर इसके दीर्घकालिक औसत से अधिक मजबूत है। खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। सर्वेक्षण सेवा क्षेत्र की करीब 400 कंपनियों को भेजे गए प्रश्नावली के जवाबों पर आधारित है।

आपूर्ति श्रृंखला में विविधता और लचीलेपन की सीमाएं

अमिता बत्रा

पिछले महीने के आरंभ में इंडो-पैसिफिक इकनॉमिक फ्रेमवर्क (आईपीईएफ) के सभी चार सदस्य देशों ने आपूर्ति श्रृंखला समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईपीईएफ की शुरुआत के 18 महीनों के भीतर ऐसा होना सराहनीय है। हाल में घटी भूराजनीतिक घटनाओं और व्यापक झटकों ने आपूर्ति श्रृंखला के कामकाज को बहुत अधिक अव्यवस्थित किया जिसका असर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह पर पड़ा। इसमें खाद्य और औषधि जैसी जरूरी चीजें शामिल हैं। जाहिर है अधिकांश विकसित और विकासशील देशों के लिए आपूर्ति श्रृंखला को व्यवस्थित करना आवश्यक है।

यह समझौता तीन नई संस्थाओं के गठन की बात करता है- आईपीईएफ आपूर्ति श्रृंखला परिषद, आपूर्ति श्रृंखला की दिक्कतों को लेकर एक प्रतिक्रिया ढांचा और एक श्रम सलाहकार बोर्ड। परिषद अहम क्षेत्रों तथा वस्तुओं को चिह्नित करेगी और क्षेत्रवार कार्य योजना तैयार करेगी जिसमें अन्य बातों के अलावा कच्चे माल के स्रोत में विविधता, संयुक्त शोध और व्यापार सुविधा आदि शामिल होंगी। नेटवर्क आपूर्ति श्रृंखला से जुड़ी संकट की स्थिति में सदस्य देश को आपातकालीन संचार चैनल मुहैया कराएगा। समूचे नेटवर्क में संभावित संकटों का समय पूर्व पता लगाने की कोशिश की जाएगी ताकि भविष्य की बाधाओं से बचा जा सके। सलाहकार बोर्ड में सरकार, कर्मचारी और नियोक्ताओं के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह श्रमिकों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा तथा इस क्षेत्र में बेहतर कार्य व्यवहार के लिए सलाह देगा।

इसके प्रावधान जहां आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं से बचने के लिए बचाव उपायों की

एक व्यापक कवरेज मुहैया कराते हैं, वहीं वे गैर बाध्यकारी हैं। ऐसे में उल्लिखित लक्ष्यों को हासिल करने की कोई गारंटी नहीं है। मानक मुक्त व्यापार समझौतों और इसमें यही प्रमुख अंतर है। प्रावधानों में कई लचीलेपन भी शामिल हैं।

खासतौर पर ऐसे हालात में जहां कोई देश अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए जानकारी नहीं साझा करना चाहता है। चूंकि बीते कुछ वर्षों में व्यापार प्रतिबंधात्मक या प्रतिगामी औद्योगिक नीति उपायों के लिए यही दलील दी गई है इसलिए समझौता यह सुनिश्चित करने में नाकाफी रह सकता है कि क्षेत्र में व्यापार व्यवस्था नियम आधारित हो और इस प्रकार आईपीईएफ के व्यापक रणनीतिक हितों को पूरा किया जा सके।

प्राथमिक रूप से अनुशंसीय इस समझौते के अन्य पहलू भी हैं जो इसके क्रियान्वयन को प्रभावित कर सकते हैं। आईपीईएफ समझौते कार्यकारी समझौते हैं और उनके लिए अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी आवश्यक नहीं है लेकिन एक अहम सवाल विभिन्न प्रशासनों के बीच इसकी व्यवहार्यता का है। खासतौर पर यह देखते हुए कि एक साल के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव होने हैं तथा पूर्व राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के हालिया बयान बताते हैं कि दोबारा चुनाव जीतने पर वह इस समझौते को विफल करेंगे।

किसी भी सदस्य देश में आपूर्ति श्रृंखला को लेकर उत्पन्न संकट से निपटने के लिए समन्वित प्रयास के लिए जरूरी आपात संचार चैनल शायद इस समझौते का सबसे अहम पहलू है। सफल क्रियान्वयन के लिए अहम कच्चे माल की मांग की सटीक मात्रा, सुरक्षा भंडार का उचित रखरखाव और सदस्य देशों तथा उनके बीच सुचारु लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने के साथ स्रोतों को विविध बनाने की आवश्यकता होगी। हालांकि इन पूर्व शर्तों को निभाना आसान नहीं।

फ्रेंड एवं अन्य द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन यह दिखाता है कि नीतिगत बातों के विपरीत आपूर्ति श्रृंखला की विविधता विभिन्न स्तरों पर उभर रही है। हालांकि 2017 से 2022 तक रणनीतिक उद्योगों (अमेरिकी सरकार द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी उत्पादों के रूप में उल्लिखित) सहित अत्यधिक विभाजित व्यापार आंकड़ों का विश्लेषण चीन के आयात पर उच्च अमेरिकी टैरिफ के असर और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर उसके असर को दिखाता है।

अब फिर से प्रति सोमवार लगेगा कलेक्टर जनचौपाल

कलेक्टर ने ली समय-सीमा की बैठक, जन समस्याओं के निराकरण करने के दिए निर्देश

सफलता पूर्वक निर्वाचन संपन्न होने पर अधिकारी-कर्मचारियों को दी बधाइी

रायपुर। कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने सभी जिला अधिकारियों को जिले में सफलतापूर्वक निर्वाचन कार्य संपन्न होने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी ने टीम भावना से कार्य किया और जो भी दायित्व सौंपा गया उसे समर्पण भाव से निर्वहन किया।

कलेक्टर ने कहा कि आचार संहिता समाप्त हो गई है, सभी विभाग जनता से जुडे कार्यों को गति प्रदान करें और जनता की समस्याओं का जल्द से जल्द निराकरण करें। अब हमेशा की तरह प्रति सोमवार सुबह 10:30 बजे दोपहर 1:30 बजे तक कलेक्टर जनचौपाल शुरू की जाएगी। जिसमें आमजनों की समस्याओं को सुना जाएगा और यथासंभव निराकरण किया जाएगा।

डॉ भुरे ने कहा कि राजस्व विभाग के सभी अधिकारी राजस्व न्यायालय में बैठना आरंभ करें और लंबित प्रकरणों का तत्काल निराकरण करें। नगर निगम नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ-सफाई, पेयजल इत्यादि की गुणवत्तापूर्व सुविधा प्रदान करें।

शिक्षा विभाग स्कूलों का संचालन नियमित रूप से करें और बच्चों की अतिरिक्त कक्षांए लेकर निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण कराएं।

निरंतर वीकली टेस्ट लें। महिला बाल विकास को आंगनबाडियों को निरंगर संचालन करें और बच्चों-महिलाओं को पूरकपोषण आहार देना सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग तथा अन्य संबंधित विभाग सड़कों की मरम्मत कार्य पूर्ण करें।

बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अबिनाश मिश्रा, सभी एडीएम-एसडीएम तथा अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

निगम दस्ते ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, अवैध चखना सेंटर को भी हटाया गया

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेन्द्र भुरे के निर्देशानुसार नगर निगम रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण अभियान चलाया गया और अवैध अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की गई। साथ ही अवैध चखना सेंटरों को हटाने की कार्रवाई की गई। आज नगर निगम के मुख्यालय उड़न दस्ता एवं जोन की नगर निवेश विभाग की टीम द्वारा पुलिस प्रशासन बल की उपस्थिति में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। विशेष टीम द्वारा सालेम स्कूल के पास दीवार के समीप अवैध रूप से व्यवसाय कर रहे लगभग 35 ठेलों को हटाकर जप्त करने की कड़ी कार्यवाही की गई। साथ ही नगर निगम की टीम ने सांध्यकालीन अभियान चलाकर जी. ई. रोड में एन. आई. टी. के समीप सड़क पर अवैध रूप से व्यवसायरत लगभग 40 अवैध ठेलों को हटा कर जप्त किया। इसके अलावा संतोषी नगर मुख्य मार्ग एवं निगम जोन 9 के क्षेत्र के विभिन्न मुख्य मार्गों में भी अभियान चलाकर विभिन्न मुख्य मार्गो को अवैध कब्जों से मुक्त करवाया गया।

बाबू भैया की कलम से

बड़ी चुनौतियों के साथ भाजपा की वापसी

छतीसगढ़ में पहली बार हिदुत्व की राजनैतिक स्थापना कवर्धा व साजा विधानसभा सीट पर साफ साफ देखी गई। अब यह सनातनी धारा इस धरा पर और तेजी से बहेगी यह दिखाई देने लगा है। इन क्षेत्रों के साथ अब यह सुगबुगाहट सम्पूर्ण छतीसगढ़ में चल पड़ेगी इसकी पूरी संभावना बन गई है। अगले चुनाव के पहले बल्कि यूं कहें कि लोक सभा के चुनाव में सनातन धर्म का जागरण तेजी से स्थानीय सनातनियों को जगा देगा तो अतिशियोक्ति नहीं होगी। कवर्धा की घटना के बाद बेमेतरा के साजा विधानसभा क्षेत्र में भूवनेश्वर साहू की हत्या को सांप्रदायिक रंग में देखा गया,इसका असर बेमेतरा ,नवागढ़ की विधानसभा के साथ छतीसगढ़ के अन्य कुछ विधानसभाओं में भी दिखाई दिया है। इस बार इस विधा को पुराने विधायक पूर्व मंत्री रहे बृजमोहन अग्रवाल ने भी एक मौके में तब्दील कर बेहतर ढंग से भुनाया और अभूतपूर्व सफलता हासिल भी की। पहले माना ये जाता था कि इस शांति के टापू पर सीधे सादे लोग रहते हैं ,उनके बीच नफरत व विभेद की व जातिभेद की राजनीति असर नहीं करती और हर चुनाव में यह दिखाई भी देता था। लेकिन इस बार कवर्धा व साजा बेमेतरा के रास्ते भाजपा का हिन्दू कार्ड प्रभाव डाल गया है। लगता था धर्मांतरण,हिदुत्व का एजेंडा नहीं चलेगा लेकिन ना सिर्फ चल गया बल्कि दिखने लगा है कि स्थापित होने लगा है। आगामी चुनाव में यह मुद्दा अब बडा मुद्दा रहेगा यह भी स्पष्ट संभावना बन गई है।

देश के दिग्गज बुद्धिजीवियों को भी भाजपा की यह आंतरिक मारक रणनीति समझ नहीं आई। सभी का आंकलन था कि कमोबेश कांग्रेस सत्ता पर लौट आएगी,सरकार बचा लेगी। क्या खुफिया विभाग ,क्या बुद्धिजीवी,क्या पत्रकार सभी परिणाम से चकित हैं। अब यही लोग कहते हैं कि शायद अपनी ग्रामीण योजनाओं के प्रभाव को असरदार मान कर कांग्रेस के मुखिया आत्ममुग्ध हो गए। वे अपने प्रदेश के अन्य शीर्ष नेताओं के मिजाज को व उनकी आंतरिक नाराजी को समझ नहीं पाए या समझना नहीं चाहा। इससे हुआ यह कि सभी सिर्फ अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में ही सिमट गये। सारा भार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने ऊपर ले लिया। लोगों को साफ समझ आ गया कि नेतागण एक नहीं है। हमारा भला कर पाएंगे या आपसी द्वंद इनमें बढ़ेगा। बस यहीं जनता असहज हो गई और विकल्प खोजने लगी ,अच्छा विकल्प भाजपा ही नजर आया। मोदी की व्यक्तिगत गारंटी भूपेश बघेल के सामूहिक घोषणा पत्र पर भारी पड़ गई। रही सही कसर महतारी वंदन योजना में 1000 प्रति शादीशुदा देने के लिए भरवाए गए लाखों फॉर्म ने पूरी कर दी। जैसे जैसे फॉर्म भरवाए गए वैसे वैसे वोट प्रतिशत भाजपा के खाते में बढ़ते गया,परिणाम में सुनामी दिखाई दे गई ।बड़ी संख्या में महिलाओं ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। युवाओं की भी नाराजी वोटों के रुझान में दिखाई दे रही हैं,किसानों ने जरूर कांग्रेस कहें या भूपेश पर भरोसा जताया है यह दिख रहा है,लेकिन इसमें भी मोदी की गारंटी में किसानों के लिए किए 20 वायदों ने सेंध मारी है, यह दिख रहा है। कुल जमा 35 सीटों में से धमतरी व भिलाईनगर के अतिरिक्त सभी सीट ग्रामीण इलाके की ही जीती है। जहां जहां स्थानीय प्रशासन में कांग्रेस के मेयर हैं लगभग सभी जगह मात मिली है। यानी यह दर्शाता है कि निगम के कार्य व वहां का नेतृत्व करने वाले नेताओं से लोगों की नाराजी रही। खास कर नजर डालें तो रायपुर ही देख लें , सातों सीटों पर पहली बार भाजपा काबिज हुई है। कांग्रेस के मेयर रहते शहर में यह स्थिति क्यों बनी इसके कारण जानने समझने की जरूरत है। बहरहाल भाजपा ने बहुमत की सरकार बनाने का रास्ता तैयार कर लिया है। आजकल में मुख्यमंत्री कौन होगा यह स्पष्ट हो जाएगा। भारी भरकम योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी अब भाजपा पर आ गई है। पहले ही महीने धान खरीदी का अपने ही कार्यकाल का दो साल का बकाया बोनस 25 दिसम्बर को ही देने का वायदा पूरा करना है। साथ ही इसीमाह से महतारी वंदन योजना की तहत प्रति शादीशुदा महिला को 1000 रुपये उनके खाते में डालने का वायदा हर हाल में पूरा करना है।धान की खरीदी 3100 में 21 क्विंटल प्रति एकड़ करनी है। एकमुश्त भुगतान करना है। यह तत्काल करने योग्य वायदे हैं। लोगों की नजर इन्हीं विषयों पर है कि यह वायदा सही तरीके से पूरा होता है या नहीं ? बाकी वायदों में समय सीमा तय नहीं है। इसके लिए समय का इन्तजार करने जनता तैयार भी होगी।

भाजपा सरकार में कानून का राज चलेगा, गुंडाराज नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद अब रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल एक्शन मूड में आते हुए दिखाई दिए। विधायक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने छोटा पारा और बैजनाथपारा पहुंची और पिछले कुछ सालों से यहां पर देर रात तक संचालित होने वाले दुकानों को रात 10-30 बजे बंद करा दिया गया। बृजमोहन ने साफ कह दिया है कि रायपुर शहर में अब गुंडाराज नहीं कानून का राज चलेगा। गुंडागर्दी करने वाले, नागरिकों को परेशान करने वाले सलाखों के पीछे जाएंगे। बृजमोहन ने कहा कि कांग्रेस राज में रायपुर के छोटा पारा और बैजनाथ पारा एक तरह से अपराधियों का गढ़ बन गया था। यहां की दुकानें देर रात तक गुलजार रहती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार के सबसे ताकतवर लोगों का यह इलाका था, यहां उनके गुर्गों की धमक थी। बेखौफ अपराधियों का यह ठिकाना रहता था। इस वजह से क्षेत्र की आम जनता त्रस्त थी। उनकी शिकायतों को कांग्रेस सरकार के दबाव में पुलिस नजर अंदाज करती थी। बृजमोहन ने कहा कि भाजपा की सरकार में लोगों की सुरक्षा का ख्याल रखना हमारा पहला कर्तव्य है। बीते 5 वर्षों में रायपुर शहर सहित संपूर्ण प्रदेश में अपराध बढ़े हैं। इन बढ़े अपराधों को रोककर लोगों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा करना बेहद जरूरी है।

अधिकारियों को पूर्व डॉ रमन की समझाइश

रायपुर. 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल चुका है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप चुके हैं. सत्ता परिवर्तन की इस प्रक्रिया के बीच आज भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर प्रशासनिक अधिकारियों को समझाइश दी है. डॉ रमन सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि, आज कुछ सूत्रों से मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई है कि प्रदेश के कुछ अधिकारी महत्त्वपूर्ण फ़ाइलों को बैक डेट अंकित कर स्वीकृत कर रहे हैं जोकि पूर्णत: अनुचित है. मैं ऐसे सभी अधिकारियों को बताना चाहता हूं कि, आप प्रशासनिक व्यवस्था के हिस्से हैं.

हमारे पास बहुमत, महापौर के खिलाफ लाएंगें अविश्वास प्रस्ताव: मीनल

रायपुर। रायपुर नगर निगम मुख्यालय में भाजपा पार्षद दल की एक महत्त्वपूर्ण बैठक हुई। जिसमें भाजपा पार्षद दल ने महापौर एजाज ढेबर से इस्तीफे की मांग की है। रायपुर नगर निगम की नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरह महापौर नैतिकता के अधार पर इस्तीफा दे। वही भाजपा पार्षद दल ने कहा कि महापौर का इस्तीफा नहीं होने पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। भाजपा पार्षद दल ने अविश्वास प्रस्ताव की तैयारियां भी शुरू कर दी है, जिसकी रूप रेखा इस बैठक में तय की गई है। बैठक में पार्टी के सभी पार्षद शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे ने आगे कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आधार तैयार किया जा रहा है। एक ओर कांग्रेस के पास फ़िलहाल बहुमत नहीं है, और दूसरी ओर नगर पालिका निगम रायपुर कांग्रेस सरकार में किए गए कार्यों सभी विफल है। जनता के लिए विकास के कामकाज तो दूर, जनता इनसे ही परेशान है। हम बहुमत साबित करके महापौर को हटाएंगे। मीनल ने निगम की मौजूदा स्थिति को बताते हुए कहा कि हमारे पास बहुमत है, हमारे 31 पार्षद है, साथ ही कांग्रेसी पार्षदों का भी सहयोग मिल रहा है। निर्दलीय पार्षदों ने भी हामी भर दी है, कांग्रेस के दो पार्षद छह साल के लिए निष्कासित भी है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

स्काईवाक की घटना को कांग्रेस का ताबूत बनाकर मैं जनता को समर्पित करूंगा

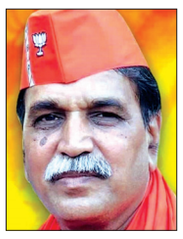

रायपुर। पूर्व लोक निर्माण मंत्री व वर्तमान में रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आमानाका चौक के पास बने चौपाटी के साथ ही स्काईवाक विवाद से प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो गई थी और कांग्रेस के लोगों ने उनके राजनीति जीवन में उनके चरित्र की हत्या करने की कोशिश की है। कांग्रेस राज में ना खाता का पता है और ना बही, उन्होंने जो कहा वो सही साबित हुआ। मूणत ने कहा कि स्काईवाक की घटना को कांग्रेस का ताबूत बनाकर मैं जनता को समर्पित करूंगा। कांग्रेस ने पूरे शहर को चौपट कर दिया ही, इसलिए कांग्रेस के हाथ से 7 सीटें चली गयी। उन्होंने कहा कि आम चुनाव के दौरान उन्होंने जनता से जो वादा किया है उसे वे पूरा करेंगे।

कांग्रेस नेता बोले, बैलेट से हो लोस का चुनाव

रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरह का हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव में हार के बाद राजनेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी हैं। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने छत्तीसगढ़ में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि 2024 में होने वाले आगामी लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस की यहां बड़ी हार हुई, जबकि भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज पांच साल बाद फिर से सत?ता में वापसी कर ली है। नतीजे के दो दिन बाद कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं, वो बेहद ही अप्रत्याशित और चौंकाने वाले हैं। विशेषतौर से छत्तीसगढ़ को लेकर जो पार्टी का आंकलन था और जो परिणाम आएं हैं। वो इस बात को साबित करने के लिए पर्याप?त हैं कि यहां कहीं न कहीं ईवीएम में गड़बड़ियां हुई हैं। यहां की जनता आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि यहां कांग्रेस की सरकार नहीं बनी है। चुनाव आयोग को इसे देखना चाहिए। उन्होंने कहा, प्रजातंत्र में यदि किसी प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं तो भविष?य में इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। कुरूद विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार ने दावा कि उन्होंने परिवार के साथ वोट डाला, लेकिन उन्हें शून्य वोट मिला।

आप-जकांछ से ज्यादा 19 विधानसभा सीटों में तीसरे नम्बर पर रहा नोटा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आए चुनाव परिणाम ने राजनीति के जानकारों को भी चौंका दिया था जिसमें सबसे चौंकाने वाली एक बात यह भी है कि प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस और बसपा को छोड़कर नोटा को सबसे अधिक वोट मिले हैं। राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त आम आदमी पार्टी को 0.93 और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे को 1.23 फीसदी ही वोट मिले जबकि नोटा को 1.26 फीसदी वोट मिले हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने अन्य को मिलाकर 12 राजनीतिक दलों के वोटों का प्रतिशत जारी की है इसमें नोटा 4 नंबर पर है। इस बार आम आदमी पार्टी और जकांछ दोनों ने सभी विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी नहीं उतरे हैं। एक वजह यह है कि भी दोनों राजनीतिक दलों को वोट प्रतिशत भी कम हुआ है। इस बार भी आम आदमी पार्टी और जकांछ दोनों किसी भी विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं जीत सकी है। जबकि पिछली बार जकांछ और बसपा ने गठबंधन किया था उनका प्रदर्शन भी शानदार था। इस बार आप और जकांछ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। कुछ ही सीटों पर दोनों दल के प्रत्याशी तीसरे नम्बर पर आएं। बता दें कि वर्ष 2013 और 2018 के मुकाबले नोटा को कम वोट मिले हैं। नोटा को सबसे ज्यादा 8620 वोट दंतेवाड़ा विधानसभा सीट में मिले हैं। चित्रकोट विधानसभा सीट में भी नोटा को 7310 वोट मिले थे।

आठ हजार से ज्यादा अवैध निर्माण इसी माह होंगे वैध

रायपुर। शहर में 8 हजार से ज्यादा अवैध निर्माण को वैध करने के आवेदन अगले साल तक लंबित नहीं रहेंगे। सभी आवेदनों का इसी माह निराकरण कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि नियमितीकरण के संबंध में समिति की बैठक हर माह की 15 तारीख को कलेक्टर लेते थे। अब तक 8 बैठकें हो चुकी है, जिनमें 10 हजार 872 अवैध निर्माणों को वैध किया गया है। इन मामलों से करीब 88.19 करोड़ रुपए मिले हैं। इस बीच आचार संहिता लगने से बैठक बंद थी और मामलों का निराकरण नहीं किया गया था। आचार संहिता हटने के बाद अब इन मामलों में तेजी आएगी। अवैध निर्माणों को वैध कराने के लिए 14 जुलाई 2022 से अगले एक साल तक आवेदन टाउन प्लानिंग विभाग और निगम के जोन दफ्तरों में लिए गए थे। बाद में इसे 12 अगस्त तक बढ़ाया गया। अंतिम माह में टाउन एंड प्लानिंग और नगर निगम के जोन दफ्तरों में 3 हजार से ज्यादा आवेदन आए। टीएनसीपी ने अचानक से बढ़े आवेदनों की संख्या को लेकर आपत्ति की थी। अभी तक कोई आवेदन को निरस्त नहीं किया गया है। अब तक 4474 अनाधिकृत निर्माण निःशुल्क नियमित किए गए हैं। 120 वर्गमीटर से अधिक के 3 हजार 164 अनाधिकृत निर्माण और 1 हजार 876 गैर आवासीय अनाधिकृत निर्माण कार्य भी अब तक नियमित किए जा चुके हैं।

अब खुलेगी घोटाले की फाइल: सीजीपीएससी परीक्षा की जांच होना तय

रायपुर. प्रदेश में सीजीपीएससी परीक्षा को लेकर खूब घमासान मचा था. अब भाजपा की सरकार बनते ही जांच होना तय है. सरकार का गठन होते ही पहली कैबिनेट बैठक में सीबीआई जांच का प्रस्ताव लाने की तैयारी होने की जानकारी है.

बता दें कि, भाजपा ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तत्कालीन चेरमैन टामन सोनवानी और कांग्रेस के कई नेताओं पर घोटाले का आरोप लगाया था. भाजपा का कहना था कि, अधिकारियों, नेताओं और ओसडी के बच्चों को गड़बड़ी करके बड़े-बड़े पद दिए गए. जिसको लेकर कोर्ट में याचिका भी लगाई गई थी. उसके बाद कोर्ट ने नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. इस मामले में पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ननकीराम कंवर ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था. साथ ही एडवोकेट संजय कुमार अग्रवाल के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि सीजीपीएससी में अधिकारी और नेताओं के बेटे-बेटियों सहित रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी जैसे पद दिए गए हैं.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जाँच के लिए 48 घंटे का समय तय किया है

विजय बघेल पाटन में आचार संहिता के उल्लंघन का मामला उठाया

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के सांसद व पाटन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी विजय बघेल और भाजपा प्रदेश मीडिया सह-प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने राजधानी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से भेंट कर पाटन विधानसभा क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश से अवगत कराया। दिल्ली हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार पर रोक की नियत अवधि के बाद भी पाटन में मुख्यमंत्री व कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल द्वारा रोड शो करके प्रचार करने को गंभीरता से लिया है।

भाजपा सांसद श्री बघेल और मीडिया सह प्रभारी श्री अग्रवाल ने मुख्यनिर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे अपने पत्र में कहा है कि इस संबंध में 16 नवंबर को चुनाव आयोग को की गई शिकायत और 24 नवंबर को इस संबंध में दिए गए स्मरण पत्र के मद्देनजर की गई जाँच के बाद निर्वाचन कार्यालय ने 29 नवंबर को जानकारी देकर यह कहा गया कि जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) पाटन एवं उडनदस्ता दल प्रभारी व नायब तहसीलदार पाटन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं पंचनामा के आधार पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होना प्रतीत नहीं होता है। श्री बघेल ने कहा कि 16 नवंबर, 2023 के आवेदन और 24 नवंबर, 2023 को दिए गए स्मरण पत्र के साथ संलग्न वीडियो एवं दो फोटो, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2023 को रोड शो के दौरान लाउडस्पीकर और वाद्ययंत्र को लेकर कांग्रेस का झंडा एवं कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का चिह्न लगा टी-शर्ट पहने दिखाई दे रहे हैं।

इस संबंध में दुर्ग के अधिकारी द्वारा जाँच नहीं की गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को सौंपे गए पत्र में मांग की गई है कि दिल्ली हाई कोर्ट के ताजा आदेश के परिप्रेक्ष्य में उक्त वीडियो व उसमें परिलक्षित व्यक्तियों की जिला प्रशासन से पृथक निर्वाचन कार्यालय के वरिष्ठ और विशेष अधिकारी की टीम से जाँच का आदेश दिया जाए और आचार संहिता के उल्लंघन का अपराध दर्ज कराया जाए।

श्री बघेल ने बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जाँच के लिए 48 घंटे का समय तय किया है। अगर उसके बाद भी न्याय नहीं मिलता तो हम फिर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

और दो दिन बारिश के आसार, ठंड बढ़ेगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान मिचौंग के प्रभाव से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। आगामी तीन दिवस के भीतर प्रदेश में बारिश के आसार जताये गए हैं। राजधानी रायपुर, धमतरी समेत आस-पास के कई जिलों में मंगलवार सुबह से बारिश शुरू है और ठंडी हवाओं के साथ ठिठुरन जारी है। प्रदेश में आज से पूरे बस्तर क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग द्वारा जताई गई है। भारी बारिश के साथ बस्तर के क्षेत्र में 20 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की उम्मीद जताई गयी है। साथ ही प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी आज हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि, आठ दिसंबर से मौसम खुलने की उम्मीद है और उसके बाद ठंड में और ज्यादा बढ़ोतरी होगी। सोमवार से रायपुर सहित पूरे प्रदेश भर में सुबह से ही बादल छाए रहे और दिनभर बादल छाने के साथ ही खाड़ी से ठंडी हवाओं के आने का क्रम जारी रहा। खाड़ी से आने वाली ठंडी हवाओं के चलते इन दिनों ठिठुरन और ज्यादा बढ़ गई है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के लोगों ने अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है।

खड़ी फसल को नुकसान- प्रदेश में बादल छाने व बारिश के चलते अधिकतम तापमान में तो काफी गिरावट की उम्मीद है, हालांकि न्यूनतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं होगा। ऐसा मौसम विशेषज्ञों का कहना है, चक्रवाती तूफान मिगजौम के प्रभाव से होने वाली इस बारिश के कारण खड़ी फसल के साथ ही कच्चे मकानों को काफी नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई गई है। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि, मौसम का मिजाज अभी चक्रवाती तूफान के प्रभाव से अगले तीन दिन ऐसा ही बना रहेगा।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.